सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

05 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा
द्वितीय सत्र

वृहस्पतिवार, तिथि 05 फरवरी, 2026 ई॰
16 माघ, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बिहार विधान सभा के स्थापना दिवस के अवसर पर 07 फरवरी, 2026 को सेंट्रल हॉल में एक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है । इस अवसर पर नेवा द्वारा बनाए गए डिजिटल हाउस का शुभारंभ भी होना है । आपसे आग्रह है कि इस व्याख्यान कार्यक्रम में अवश्य आयें । आपको आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है । डिजिटल हाउस के शुभारंभ के बाद ही आप इस टैब से सूचनाओं को ऑनलाईन देख सकेंगे, अभी इसे ऑन करने की आवश्यकता नहीं है । इसके साथ एक और सूचना देनी है कि अगर आपलोगों को कोई बात कहनी हो तो अपनी सीट के सामने लगे माइक को ऑन करें, पहले हरी लाइट जलेगी, अगर आपको आसन से अनुमति मिलती है तो लाल लाइट में बदल जायेगा उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1, श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या–219, गोह)

(लिखित उत्तर)

श्री रामकृपाल यादव, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक।

बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में दलहन प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। National Institute of Nutrition के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 25 ग्राम प्रति व्यक्ति/दिन दाल की आवश्यकता होती है, जबकि बिहार राज्य में दाल के उत्पादन से प्रत्येक व्यक्ति को 8.25 ग्राम/दिन दाल उपलब्ध हो पाता है।

यह स्वीकारात्मक है कि वर्तमान में राज्य में दलहन के कुल खपत का 33 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है। इसमें वृद्धि हेतु कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दलहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दलहन की खेती को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष विशेष मिशन ''दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन'' लागू किया गया है जिसके लिये कुल 93.75 करोड़ रूपये आवंटित की गयी है साथ ही राज्य योजना 30.00 करोड़ रूपये व्यय का लक्ष्य निर्धारित है। दलहन के बीज प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य में बीज उत्पादन की कार्ययोजना तैयार की गयी है जिसमें 45922 क्वीं0 प्रमाणित बीज उत्पादन एवं 2043 क्वीं0 आधार बीज का उत्पादन किया जायेगा जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त 115742 क्वीं0 नये प्रभेदों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे 4.14 लाख हे0 में दलहनी फसलों का क्षेत्र विस्तार संभावित है।

साथ ही प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु अनुदानित दर पर दलहन प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, विपणन की व्यवस्था आदि के माध्यम से दलहन उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद पर उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसान दलहन उत्पादन हेतु प्रोत्साहित हों।

विभाग द्वारा आगामी 5 वर्षों में दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु वर्तमान आच्छादन 4.48 लाख को बढ़ाकर 9.19 लाख हेक्टेयर तथा वर्तमान उत्पादकता 3.93 लाख मि0ट0 को बढ़ाकर 11.27 लाख मि0ट0 करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है ताकि राज्य दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है, पूरक पूछिए ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य में दलहन की कुल खपत का 33 प्रतिशत ही उत्पादन हो रहा है । माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितनी राशि खर्च करके कौन सी योजना कार्यान्वित की गई है ।

श्री रामकृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, दलहन बिहार की कृषि व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण फसल है । वर्ष 2024–25 में राज्य में लगभग 4.48 लाख हे0 क्षेत्र में दलहन की खेती से 3.93 लाख मि0ट0 का उत्पादन प्राप्त हुआ है । यह हमारे किसानों की मेहनत, माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत दलहन को विशेष प्राथमिकता दी गई है । अनुदानित दर पर बीज वितरण आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रत्यर्क्षण कार्यक्रम तथा ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव जैसे उपायों से दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2024–25 में मसूर उत्पादक किसानों को 2000 प्रति क्वि0 की प्रोत्साहन राशि दी गई है तथा मूंग को हरित खाद के रूप में विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है । माननीय मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत दलहन के बीज प्रतिस्थापन दर में उल्लेखनीय वृद्धि है । माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दलहन की आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत बिहार को 93.75 करोड़ की राशि आवंटित की गई है । उससे उन्नत बीज उत्पादन, क्षेत्र विस्तार, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन को बल मिला है । सरकार द्वारा नाफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के माध्यम से एम0एस0पी0 दर दलहन की सुनिश्चित खरीद की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को उनकी उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में दलहन के क्षेत्र उत्पादन को दुगुना से अधिक बढ़ाकर बिहार को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जायेगा और किसानों की आय को सशक्त एवं सुरक्षित किया जायेगा । सरकार हर कदम पर किसानों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सर्वजीत जी आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य अमरेन्द्र जी, आप दो पूरक और पूछ लीजिए ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार औरंगाबाद के गोह विधान सभा में दलहन के बीज का उत्पादन केंद्र और दलहन की प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, वितरण की व्यवस्था कब तक कराना चाहती है ?

श्री रामकृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी तौर पर सरकार की मंशा को मैंने यहां स्पष्ट रूप से रखा है और आगे भी जहां भी आवश्यकता होगी औरंगाबाद सहित बिहार के किसी भी इलाके में अगर मेरे संज्ञान में आयेगा, सरकार के संज्ञान में आयेगा तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : महोदय, समय तो बता दिया जाय ।

श्री रामकृपाल यादव, मंत्री : समय, यथाशीघ्र होगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर होने की व्यवस्था होती है तो टाल इलाका में दलहन की खेती होती है, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या टाल इलाका में जो जल से भरा पड़ा रहता है पूरा जिसके चलते बिहार के किसान दलहन का उत्पादन नहीं कर पा रहा है क्या सरकार उन किसानों को जो टाल इलाका पूरा पानी से भरा रहता है उसका कोई निवारण हुआ या नहीं । वर्षों से चला आ रहा है कि हम उसका निवारण करेंगे । दूसरा है महोदय कि किसानों को गेहूं और चावल, आप एम0एस0पी0 खरीद रहे हैं, बिहार में कहीं भी कोई जिला नहीं है जहां पर आप एम0एस0पी0 पर दलहन की खरीद करते हैं तो आखिर किसान दलहन की खेती कैसे करेगा, आप किसान की दाल खरीद नहीं सकते हैं । टाल इलाका से पानी निकालने की आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं । दलहन के उत्पादन का बढ़ावा आप बिहार में कैसे दे सकते हैं यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं ।

श्री रामकृपाल यादव, मंत्री : माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं और शायद आप सबलोगों को पता होगा कि लंबे काल तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं और स्वयं रुचि लेकर के जो वहां जलजमाव की समस्या है जिसकी वजह से किसान प्रभावित होता है, सारी चीजें उनके संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जल संसाधन विभाग के माध्यम से मिल–बैठकर इसके निदान के लिए सरकार प्रयास कर रही है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने टाल इलाके और उसमें जो जलजमाव की स्थिति होती है उससे मुक्ति के विषय में बात रखी है और चूंकि यह जल संसाधन विभाग से संबंधित है । माननीय सदस्य का यह कहना शत–प्रतिशत सही है कि टाल का इलाका दलहन के उत्पादन के लिए मशहूर

है और वहां से काफी मात्रा में दलहन का उत्पादन होता है और सरकार टाल इलाके से जल निकासी ही नहीं, पूरे टाल क्षेत्र के समेकित विकास की योजना पर काम ही नहीं कर रही है उसका चरणबद्ध क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर चुकी है । उसमें दो तरह की स्थिति है, एक तो जितना अतिरेक जल है, सरप्लस वाटर है उसकी निकासी की व्यवस्था की जा रही है और थोड़ा चूंकि जान रहे हैं महोदय, जल–जीवन–हरियाली कार्यक्रम के तहत थोड़ा जल ये जल संग्रहण क्षेत्र में रखना भी जरूरी होता है जिससे भूजल क्षेत्र की रिचार्जिंग हो सके । उतना छोड़कर बाकी पर हमलोग काम कर रहे हैं, उसके लिए हरोहर नदी के माध्यम से जो गंगा में अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था है उसके लिए हमलोग बालगुदर में एंटी प्लस स्लुईस गेट का भी निर्माण करा रहे हैं और आपकी जो चिंता है जायज है, सरकार उसपर काम कर रही है, समयबद्ध तरीके से उसका निदान हो जायेगा ।

अध्यक्ष : एक जानकारी देना चाहेंगे, मेरी जानकारी में है कि राज्य सरकार और भारत सरकार के सहयोग से बिहार में दलहन क्रय की योजना भी शुरू की गई थी । सर्वजीत जी, आप बोलिए ।

टर्न–2 / मुकुल / 05.02.2026

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धान और गेहूं की खरीद एम0एस0पी0 पर अगर सरकार कर रही है और दलहन की खरीद एम0एस0पी0 पर अगर सरकार नहीं कर रही है । आप सब जानते हैं कि दलहन की खेती मानव जीवन के लिए कितना जरूरी है तो क्या किसानों को खुशहाल करने के लिए दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार एम0एस0पी0 पर दलहन की खरीद करना चाहती है या नहीं चाहती है, हम यह जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : बिहार के किसान दलहन की खेती भी कर रहे हैं मेरी जानकारी में जो है और साथ–साथ चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र और बिहार सरकार के सहयोग से यह काम परचेजिंग का हो गया है एम0एस0पी0 रेट पर और मैं समझता हूं कि सारी बात आ गयी है और माननीय मंत्री जी ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है पांच वर्षों का लक्ष्य है और जो लक्ष्य है उसे ये पूरा करेंगे । माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री अपने हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार देख रही है, सरकार इसकी चिंता कर रही है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शांति–शांति ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–2 (मोहम्मद मुर्शिद आलम, क्षेत्र सं0–50 , जोकीहाट)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : 1. अस्वीकारात्मक ।

भारत सरकार द्वारा धान एवं गेहूं की तरह मक्के का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है । विदित हो कि खरीफ विपणन मौसम–2025–26 में भारत सरकार द्वारा मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400/– प्रति क्वी0 निर्धारित किया गया है ।

2. अस्वीकारात्मक ।

बिहार राज्य अन्तर्गत रबी विपणन मौसम 2024–25 में केन्द्रीय अभिकरण एन0सी0सी0एफ0 एवं सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन प्रखंड स्तर पर कार्यरत व्यापार मंडल के माध्यम से मक्का अधिप्राप्ति प्रारंभ की गयी थी । परन्तु बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहने के कारण अधिप्राप्ति नहीं हो सकी। साथ ही रबी विपणन मौसम 2025–26 में इथेनॉल उत्पादन ईकाइयों द्वारा एन0सी0सी0एफ0 से मक्के की मांग नहीं किये जाने के कारण राज्य अन्तर्गत अधिप्राप्ति प्रारंभ नहीं की गयी थी ।

3. आगामी रबी विपणन मौसम 2026–27 में इथेनॉल उत्पादन ईकाइयों द्वारा एन0सी0सी0एफ0 से मक्के की मांग प्राप्त होने के उपरांत राज्य अन्तर्गत अधिप्राप्ति माह जून, 2026 से संभावित है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

मोहम्मद मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, मक्का की खरीददारी के संबंध में माननीय मंत्री जी से एक जवाब आया है कि 2024–25 में मक्का की खरीददारी बिहार सरकार के द्वारा की गयी है और जवाब में सर यह आया है कि जो प्रखंड स्तर का व्यापार मंडल है और पंचायत स्तर का जो पैक्स है उनके माध्यम से किया गया है । इस संबंध में मुझे कहना है कि मंत्री जी जो 2024–25 की बात कर रहे हैं इसकी चिट्ठी मेरे पास है जिसका पत्रांक, ज्ञापांक–420, दिनांक–25.03.2025 का है और मंत्री जी अभी जो कह रहे हैं कि हम 2024 में खरीदे हैं इसका ज्ञापांक–2846, दिनांक–04.06.2024 का है लेकिन इसमें जो है इन्होंने खरीददारी की जो बात कही है मात्र इनका जो एक आदेश हुआ बिहार सरकार की अधिसूचना के माध्यम से वह व्यापार मंडलों को, पैक्स को नहीं दिया गया है इसमें जो जानकारी दी गयी है कि पैक्स के माध्यम से खरीददारी की गयी है एक तो यह गलत है शायद किस वजह से । अगर यह दूसरी चिट्ठी है तो वह भी हमको दें और इसका जो एक यह होता है मक्का का सर कि एक महीना का समय दिया गया है कि दिनांक–05.06.2024 से दिनांक–05.07.2024 तक मक्का की जो खेती होती है वह थोड़ा जो अक्टाव होता है, जो बोआई होता है वह मार्च के बाद कटने लग जाता है । आप खरीददारी कर रहे हैं जून में तो कहीं न कहीं इसका समय भी बढ़ाने की जरूरत है और दूसरी बात है कि इसमें एक महीना का जो समय दिया गया है मक्का की खेती के लिए, उसकी खरीददारी के लिए लम्बा समय दिया जाय और इसका एक जवाब आया है कि हमलोग 2025–26 में भी मक्का की खरीददारी के लिए ये किये हैं । लेकिन उसकी जो चिट्ठी ज्ञापांक–420, दिनांक–25.03.2025 को उसमें कहीं भी मक्का का कोई जिक्र नहीं है कि मक्का खरीददारी का हम कर रहे हैं और एक सवाल यह भी है कि क्या मक्का की खरीददारी सरकार करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्पष्ट है लगता है माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया । यह बात सही है कि वर्ष 2024–25 में मक्का अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था और न्यूनतम समर्थन मूल्य 2090 था और उस समय मार्केट रेट में, बाजार में इससे अधिक प्रति क्विंटल ज्यादा मूल्य था इसलिए यह अधिप्राप्ति नहीं हो सकी । रही बात 2025–26 में चूंकि रबी विपणन मौसम वर्ष 2025–26 में इथेनॉल उत्पादन ईकाइयों के द्वारा एन0सी0सी0एफ0 के द्वारा मक्के की मांग नहीं की गयी थी इसलिए एन0सी0सी0एफ0 के द्वारा अधिप्राप्ति प्रारंभ नहीं की गयी और आगामी रबी विपणन मौसम 2026–27 में इथेनॉल उत्पादन ईकाइयों द्वारा एन0सी0सी0एफ0 से मक्के की मांग प्राप्त होने के उपरांत राज्य अन्तर्गत अधिप्राप्ति माह जून, 2026 से संभावित है । अध्यक्ष महोदय, यह डिमांड पर है, इथेनॉल कम्पनी डिमांड करेगी तभी अधिप्राप्ति होगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

मोहम्मद मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है कि ध्यान नहीं दिया गया, इनके जवाब में है कि पैक्स द्वारा भी खरीददारी की गयी है वर्ष 2024 में, लेकिन सर चिट्ठी में स्पष्ट है यहां पर कि मात्र व्यापार मंडल को ही आदेश दिया गया है और इसका व्यापक न प्रचार–प्रसार कहीं भी प्रखंड स्तर से मक्के की खरीददारी के लिए नहीं की गयी है और यह कह रही हैं कि ठीक है इसका जो समर्थन मूल्य बाजार में ज्यादा था मेरा कम था 2090 इस वजह से खरीददारी नहीं हुई है, कम से कम किसानों को जानकारी मिलनी चाहिए कि व्यापार मंडल या पैक्स के माध्यम से खरीददारी हो रही है, ऐसा मेरा मानना है कि कहीं भी किसी माननीय सदस्य को यह जानकारी नहीं है और हमें इसलिए आपत्ति हुआ कि आप व्यापार मंडल को कहते हैं लेकिन जवाब में लिखते हैं कि पैक्स को भी आदेश दिया गया है तो पैक्स का नाम कहीं भी नहीं है इस चिट्ठी में, सिर्फ व्यापार मंडल है सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के सुझाव की समीक्षा कर लीजिए और करके....

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसका प्रचार–प्रसार भी किया गया था । यह बाजार में प्रति क्विंटल अधिक मूल्य था इसलिए नहीं हो पाया, प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से ही अधिप्राप्ति होना था ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का आग्रह है कि पैक्स भी खरीदे । आप इसकी समीक्षा कर लीजिए, समीक्षा करके इसे संभव कीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है कि सीमांचल क्षेत्र में काफी बड़े हिस्से में मक्का की खेती होती है और वहां के किसानों के लिए एक वरदान है ये कि कैश क्रॉप है और उसकी बुआई नवंबर, दिसम्बर और जनवरी तक होती है और कटाई भी इसी तरह से तीन महीना लेट होती है तो तीन महीने तक जिस फसल की कटाई हो सर उसकी खरीददारी सिर्फ एक महीने के लिए देना यह कहीं से उचित नहीं है और दूसरी बात माननीय मंत्री महोदया ने कहा है कि इथेनॉल कम्पनी वाले का चूंकि ऑर्डर नहीं था, उनकी मांग नहीं थी इसलिए खरीददारी नहीं हुई तो सरकार समर्थन मूल्य अगर तय करती है तो इसीलिए न

तय करती है कि बाजार में खरीददारी नहीं हो तो सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों की खरीददारी करे तो क्या ऐसी पॉलिसी बनायेंगे कि उसकी तीन महीने तक खरीददारी हो, इथेनॉल कम्पनी मांगे या न मांगे लेकिन उसकी खरीददारी सरकारी स्तर पर करायी जाए । क्या इसका उपाय माननीय मंत्री महोदया करायेंगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने साफ कहा है, हमारे द्वारा बताया जा रहा है, आप सबों का जो सुझाव आया है उसकी माननीय मंत्री जी आप समीक्षा कर लीजिए और समीक्षा करके जो संभव हो उसे करने का प्रयास करें ।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–108 (श्री बिजय सिंह, क्षेत्र सं0–68, बरारी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : स्वीकारात्मक ।

उक्त योजना की स्वीकृति भारत सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं है ।

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो प्राप्त हुआ है । सरकार ने अपने जवाब में स्वीकारात्मक भी कहा है । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहूंगा कि चूंकि काढ़ागोला घाट पूरे सीमांचल का एक ऐसा घाट है जहां अररिया, पूर्णिया, किशनगंज से लोग आते हैं, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि प्राथमिकता के आधार पर इस फाइनेंसियल ईयर में उस छठ घाट का, काढ़ागोला घाट का निर्माण कराया जाय ताकि वहां पर जिस तरह से सिमुराई घाट का निर्माण कराया गया है, सीमांचल के क्षेत्रों में उस घाट का निर्माण कराया जाए ताकि लोग वहां पर आकर सुनियोजित ढंग से पूजा–अर्जन कर सकें, चूंकि माघ पूर्णिमा में काफी लोग वहां आते हैं लाखों–लाखों की संख्या में, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार से लोग आते हैं तो उस छठ घाट का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो कहा गया है हमने भारत सरकार को भेजा भी है और वहां से प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद वह कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

श्री बिजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी काफी काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि नगर विकास से इस काम को आपके प्राथमिकता के आधार पर प्रथम काम कराया जाय, यह हमलोगों का धरोहर है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : ठीक है, हम इसको दिखवाते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–109 (श्री अमरेन्द्र कुमार, क्षेत्र सं0–219, गोह)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : 1. अस्वीकारात्मक ।

कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा वर्ष 2024–25 में औरंगाबाद का अनुमानित धान उत्पादन 1037169 मीट्रिक टन प्रतिवेदित किया गया था तथा भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था, इसलिए औरंगाबाद के लिए धान अधिप्राप्ति लक्ष्य 312719 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था ।

2. अस्वीकारात्मक ।

वर्ष 2025–26 में कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा औरंगाबाद जिला का अनुमानित धान उत्पादन 724667 मीट्रिक टन प्रतिवेदित किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति लक्ष्य 36.85 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जिसके आधार पर औरंगाबाद जिला का धान अधिप्राप्ति लक्ष्य 170902 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है ।

3. प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम में राज्यान्तर्गत कृषि विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुमानित धान उत्पादन आंकड़ों एवं भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए निर्धारित धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के आधार पर जिलावार धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा गत वर्ष 2024–25 के लिए राज्य में किसानों से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया था जबकि इस वर्ष इसे घटाकर 36.85 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है जिससे राज्य के किसानों को अपना धान औने–पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है सरकार इसके लिए क्या कर रही है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्रीमती लेशी सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है हमलोग संपर्क में हैं सरकार और विभाग । तो उम्मीद है कि हमलोग लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं और मिलने भी जायेंगे और अनुरोध भी कर रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न–3 / सुरज / 05.02.2026

(क्रमशः)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : जैसे ही वहां से लक्ष्य बढ़ेगा हमलोग जिले का भी लक्ष्य बढ़ायेंगे ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार के जवाब वर्ष 2025–26 के लिये औरंगाबाद जिले में अनुमानित धान उत्पादन 07 लाख 24 हजार 667 मीट्रिक टन बताया गया है । जबकि औरंगाबाद के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–2524, दिनांक–04.01.2025 के द्वारा धान का अनुमानित उत्पादन 11 लाख 60 हजार 584 मीट्रिक टन प्रतिवेदित है । सरकार का जो जवाब आया था उसमें वह जवाब गलत है ।

अध्यक्ष : सरकार प्रयास कर रही है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, धान अधिप्राप्ति सरकार का एक अहम हिस्सा है । एफ0आर0के0 की वजह से धान का जो सी0एम0आर0 देना रहता है, वह सी0एम0आर0 नहीं जा रहा है जिस प्रतिशत में जाना चाहिये । औरंगाबाद में भी मात्र 8 परसेंट अब तक वहां पर चावल की अधिप्राप्ति हो पाया है । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि एफ0आर0के0...

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य ने कहा है कि यह जो आंकड़ा है उत्पादन का, यह गलत है । यह सही है, कृषि विभाग का जो रिपोर्ट रहता है उसी को हमलोग मानकर चलते हैं । एफ0आर0के0 की जो समस्या है इसमें भारत सरकार खुद लैब में जांच कर रही है और उसके बाद यहां पर दिया जाता है । हमलोग संपर्क में हैं, अनुरोध कर रहे हैं जल्द इसका समाधान भी हो रहा है धीरे–धीरे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बात आगे बढ़ गयी । माननीय सदस्य, श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–110 श्री मुरारी प्रसाद गौतम, (क्षेत्र सं0–207, चेनारी (अ0जा0)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत रोहतास प्रखंड के रोहतासगढ़, रसलपुर, तेलकप पंचायत एवं नौहट्टा प्रखंड के यदुनाथपुर, भदारा, साहपुर पंचायतों के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ जगहों पर भू–जल में फ्लोराइड की उपलब्धता पाई गयी है । जिसके निराकरण हेतु रोहतास प्रखंड के गुणवत्ता प्रभावित 06 वार्डों में तथा नौहट्टा प्रखंड के 8 वार्डों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट का अधिष्ठापन कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजलापूर्ति मुहैया करायी जा रही है ।

रोहतास प्रखंड के तेलकप पंचायत में कुल 7 अदद वार्ड (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) है जिसमें से वार्ड सं0–3 एवं 4 गुणवत्ता प्रभावित वार्ड है । उक्त दोनों वार्डों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट सहित जलापूर्ति योजना का निर्माण कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजलापूर्ति मुहैया करायी जा रही है । गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्ड संख्या–1, 2, 5, 6 एवं 7 में वार्ड वार जलापूति योजना का निर्माण कर नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है ।

करमा ग्राम रोहतास प्रखंड के तुम्बा पंचायत के वार्ड सं0–9 अंतर्गत आता है जो कि गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्ड है । उक्त वार्ड में नल जल योजना के माध्यम से सुचारू रूप से ग्रामीणों को पेयजलापूर्ति मुहैया करायी जा रही है ।

साथ ही पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला जल जांच प्रयोगशाला, सासाराम तथा अवर प्रमण्डलीय जल जांच प्रयोगशाला, डेहरी ऑन सोन एवं बिक्रमगंज द्वारा नियमित रूप से पेयजल की जांच की जाती है ।

वर्तमान में पेयजल की कोई समस्या नहीं है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है लेकिन जो जवाब आया है, विभाग द्वारा जो प्रस्तुत किये गये हैं गलत और भ्रामक हैं । वस्तुस्थिति कुछ और ही है ।

वहां नल–जल की जो स्थिति है काफी भयावह है । हमारे यहां पी0पी0सी0एल कारखाना हुआ करती थी जिसकी वजह से तेलकप पंचायत के सभी वार्डों में वहां का पानी काफी दूषित है और जलापूर्ति की बात जो जवाब में आया है यह सुचारू रूप से जारी है । मैं लगातार क्षेत्र भ्रमण में रहता हूं । किसी भी गांव में, तेलकप पंचायत ही नहीं पूरे रोहतास, मैं पूरे विधान सभा की बात कह रहा हूं । किसी भी गांव में आज तक जलापूर्ति पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं की गयी है । क्या माननीय मंत्री महोदय, ऐसे जो पदाधिकारी जवाब दिये हैं, उन पर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ?

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं चूंकि सदन में चुनाव जीतकर आने के बाद पहली बार मुझे आज बोलने का मौका मिला है । साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने महुआ के देवतुल्य जनता का, जिन्होंने मुझे इस सदन में चुनाव जीताकर भेजने का काम किया । साथ ही अपने पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को भी नमन करता हूं जिनकी पार्टी से मैं चुनाव जीतकर आया और साथ ही...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : चूंकि....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति । बोलने दीजिये ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : चूंकि पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला है । बहुत सारे हमारे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे हमारे माननीय सदस्य होंगे जो नहीं जानते होंगे इसलिये मैं बताना चाहूंगा कि हम जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से जीतकर आये हैं । जो हमारे नेता, देश के केन्द्रीय मंत्री, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं जिन्होंने मुझे जीताकर यहां भेजने का कम किया । साथ ही, हम माननीय सदस्य को बताना चाहेंगे कि रोहतास जिला अंतर्गत रोहतास प्रखंड के रोहतासगढ़, रसलपुर में जो तेलकप पंचायत एवं नौहट्टा प्रखंड का इन्होंने जिक्र किया है वहां पर यदुनाथपुर, भदारा और साहपुर पंचायत है । तीनों ही सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ जगहों पर भूजल में फ्लोराइड की उपलब्धता पायी गयी है । जिसके निराकरण हेतु रोहतास प्रखंड के गुणवत्ता प्रभावित 6 वार्डों में तथा नौहट्टा प्रखंड के 8 वार्डों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट का अधिष्ठापन कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया करायी जा रही है । साथ ही, रोहतास प्रखंड के तेलकप पंचायत में कुल 7 अदद वार्ड हैं, जिसमें 1 से लेकर 7 में जिसमें से वार्ड सं0–3 एवं 4 जो है वह गुणवत्ता प्रभावित वार्ड पायी गयी है । उक्त दोनों वार्डों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट सहित जलापूर्ति योजना का निर्माण कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजलापूर्ति मुहैया

करायी जा रही है और गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्ड संख्या–1, 2, 5, 6 एवं 7 में वार्ड वार जलापूति योजना का निर्माण कर नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है ।

वहीं पर करमा, रोहतास प्रखंड जो उसमें तुम्बा पंचायत के वार्ड सं0–9 अंतर्गत आता है जो कि गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्ड है । उक्त वार्ड में नल जल योजना के माध्यम से सुचारू रूप से ग्रामीणों को पेयजलापूर्ति मुहैया करायी जा रही है ।

साथ ही पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला जल जांच प्रयोगशाला, सासाराम एवं अवर प्रमण्डलीय जल जांच प्रयोगशाला, डेहरी ऑन सोन एवं बिक्रमगंज द्वारा नियमित रूप से पेयजल की जांच की जाती है ।

वर्तमान में पेयजल की कोई समस्या नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमलोग लगातार, हमारे पदाधिकारी वहां पर जाकर सभी जगह पर जब माननीय सदस्य का प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ उसके बाद हमारे जो पदाधिकारी हैं वहां पर घुमकर देखने का काम कर रहे हैं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, जिस तेलकप, करमा की बात हो रही थी वार्ड नं0–9 की, कि सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति हो रही है उसका फोटोग्राफ हमारे पास है महोदय । वहां पर जो मोटर लगा हुआ है वह आज तक चालू ही नहीं हुआ है । ऐसे ही भदारा की बात किया जाए तो वहां भी वही स्थिति है, तिलोखर की भी वही स्थिति है । किसी भी वार्ड में कहीं भी जलापूर्ति सुचारू रूप से नहीं चालू है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप ऐसा है कि...

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : महोदय, तेलकप पंचायत के वार्ड नं0–1 की जो बात हो रही है आज तक वहां किसी भी प्रकार के पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पायी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके पास जो पेपर है वह माननीय मंत्री जी को दे दीजिये । माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लेंगे ।

श्री वशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या उस पेपर में पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा है ऐसा दिख रहा है क्या ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी एक बार इसकी समीक्षा कर लीजिये ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप जो कहना चाह रहे हैं वह रिकार्ड में आ गया है । पेपर दे दीजिये, माननीय मंत्री जी समीक्षा करके निश्चित तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे...

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : महोदय, रिकार्ड में आने से काम चल जाता तो इससे पहले भी हमलोगों ने सदन में इस बात को रखा है । अभी तक तेलकप पंचायत के वार्ड नं0–1 की सिर्फ बात करें तो वहां आज तक नल जल की व्यवस्था नहीं हो पायी है ।

अध्यक्ष : आपके सारे सुझाव का माननीय मंत्री जी समीक्षा करके उसका समाधान करेंगे ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : महोदय, आपके माध्यम से आपका संरक्षण चाहूंगा कि हमारे नौहट्टा प्रखंड में ही जरादाग में एक बोरिंग करके कैमूर जिले के अधौरा और भगवानपुर

को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है मेरे ही विधान सभा के नौहट्टा प्रखंड से जारादाग में । लेकिन जिस प्रखंड में यह बोरिंग हो करके अधौरा और भगवानपुर में जा रही है, उस प्रखंड में क्या सरकार पेयजल की व्यवस्था करना चाह रही है ? दर्जनों पहाड़ी गांव है, वहां पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था सरकार करना चाह रही है ?

अध्यक्ष : आपके सुझावों का माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया है, समीक्षा करने के बाद समाधान किया जायेगा ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से हम जवाब चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था हमारे ही प्रखंड से कैमूर में जा रही है तो क्या वहां यह व्यवस्था करने के लिये तैयार हैं ?

अध्यक्ष : यह विषय जो है सासाराम का है...

(व्यवधान)

आप बोलिये ।

(व्यवधान)

जिनको अनुमति दी जायेगी वही बोलेंगे । शांति बनाए रखिये ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, इससे अच्छी योजना कुछ नहीं हो सकती है लेकिन कुछ पदाधिकारी जो हैं उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं । एक बहेरी में पी0एच0ई0डी0 का अपना नल जल है, सवा महीना से वह खराब है और बंद है । सबका ध्यान आकृष्ट कराया हूं लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है इसलिये आवश्यकता है कि सभी पदाधिकारियों का मंत्री महोदय गंभीरता से दिखवा लें ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : श्री आदित्य कुमार ।

आपका विषय पूरा रिकार्ड में आ गया ।

(व्यवधान)

आप ध्यानाकर्षण में ले आइये ।

(व्यवधान)

अभी तारांकित प्रश्न है । हमारा सुझाव है...

(व्यवधान)

टर्न–4 / धिरेन्द्र / 05.02.2026

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री श्री श्रवण बाबू, बोलिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्नकर्ता सदस्य ही अभी पूछ रहे हैं तो माननीय सदस्य उत्तेजना में क्यों आ रहे हैं ? माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उनका जो सप्लीमेंट्री है उसका जवाब सरकार दे रही है और माननीय सदस्य लोग इस तरह से हंगामा खड़ा कर रहे हैं । थोड़ा धैर्य रखिये, इस तरह से नहीं होता है । सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और आप हंगामा करना चाहते हैं...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, ये सरकार का उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं, समाधान नहीं चाहते हैं, यही आपका मकसद है तो यह मकसद रहेगा तो सरकार के मंत्री जवाब कैसे देंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठिये । माननीय सदस्य श्री आदित्य कुमार ।

(व्यवधान जारी)

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जाँच करवा देता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें । यदि माननीय सदस्यों को लगता है कि यह मामला पूरे बिहार का है तो हम चाहेंगे कि आप ध्यानाकर्षण ले आइये।

तारांकित प्रश्न संख्या–111, श्री आदित्य कुमार (क्षेत्र संख्या–92, सकरा (अ॰जा॰))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या–112, श्री अरूण मांझी (क्षेत्र संख्या–189, मसौढ़ी (अ॰जा॰))

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग । श्री अरूण मांझी जी का है, क्वेश्चन नं॰–112, नाला निर्माण के संबंध में है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्वीकारात्मक है । वर्तमान में नगर परिषद् द्वारा यह योजना प्रस्तावित नहीं है । प्रस्ताव आने पर विचार किया जायेगा ।

श्री अरूण मांझी : अध्यक्ष महोदय, बरसात के दिनों में वहां ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि एक महीना उस इलाके से निकलना मुश्किल हो जाता है । अगर नाला निर्माण नहीं कराया जायेगा और घनी आबादी बढ़ जायेगी तो आगे चल कर नाला निर्माण कराने का फिर जगह नहीं बचेगा । इसलिए वह नाला निर्माण कराना अति आवश्यक है । मैं मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इसका सर्वेक्षण कराकर नाला का निर्माण करायें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमने तो कहा कि प्रस्ताव आयेगा तो सरकार विचार करेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–113, श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या–188, फुलवारी (अ॰जा॰))

(लिखित उत्तर)

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1–आंशिक स्वीकारात्मक । पटना जिला अन्तर्गत पटना सिटी, मुसल्लहपुर, दानापुर, बिहटा, फतुहॉ, बाढ़ एवं मोकामा में कृषि बाजार प्रांगण स्थित है । फुलवारी एवं पुनपुन प्रखण्ड के किसानों हेतु नजदीक में मुसल्लहपुर बाजार प्रांगण उपलब्ध है ।

इसके अतिरिक्त प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर ग्रामीण मंडी के सुदृढ़ीकरण का कार्य सात निश्चय कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, जिसमें पुनपुन के जाहिदपुर ग्रामीण मंडी भी शामिल है ।

2–बिहार राज्य कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 लागू है तथा बाजार समिति को निरसित किया गया है । ऐसे में नयी मंडी का निर्माण की जगह पुरानी जर्जर मंडियों में जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है । प्रखण्ड स्तरीय तथा ग्रामीण हाट एवं मंडी की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है । ग्रामीण मंडी के तहत राजस्व विभाग की सूची में पुनपुन के जाहिदपुर मंडी को विकसित करने की योजना है । हाट बाजार एवं मेला के तहत ग्रामीण मंडी के विकास हेतु प्राप्त सूची में फुलवारी प्रखंड के हिन्दुनी शामिल नहीं है । वर्त्तमान में नये मंडी को बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । पटना जिला के मुसल्लहपुर एवं बिहटा बाजार प्रांगण के आधुनिकीकरण के कार्य को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा किया जा रहा है । कृषि विभाग द्वारा इसकी निरंतर समीक्षा की जा रही है ताकि कार्य में अपेक्षित प्रगति लायी जा सके । आधुनिकीकरण एवं विकास से इस बड़े बाजार प्रांगण का उपयोग पटना, फुलवारीशरीफ एवं पुनपुन के किसानों के लिए बेहतर ढंग से हो सकेगा ।

3– उपरोक्त कंडिका–01 एवं 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछ लीजिये ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जवाब आया है लेकिन जवाब में जो बात है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ । इसीलिए मुसल्लहपुर से, ये कह रहे हैं कि मुसल्लहपुर बाजार समिति से लोग जाकर बाजार कर सकते हैं लेकिन फुलवारी से और पुनपुन से, वहां से जो किसान, 20 हजार से ज्यादा किसान हैं उन किसानों को मुसल्लहपुर जाने के लिए, नो एंट्री के कारण एक भी किसान वहां नहीं जा पाते हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि फुलवारी और पुनपुन के किसान मुसल्लहपुर में जाकर कितने लोगों ने व्यापार किया है ? नहीं किया है तो बिचौलियों के हाथ में उत्पादन जा रहा है, जिसके कारण किसान और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : आप भी हैं उसी में । मेरे पुराने भाई हैं आप ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनायें ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार सरकार किसानों को उनकी फसल का बेहतर बाजार व्यवस्था उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और साथ ही इसके लिए काम भी कर रही है । वर्ष 2006 में ए॰पी॰एम॰सी॰ एक्ट के विघटन के बाद राज्य के 54 कृषि बाजार प्रांगण, निःशुल्क बाजार के रूप में कार्य कर रहे थे । वर्तमान सरकार ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से आधुनिक मॉडल कृषि बाजार प्रांगण के रूप में

विकसित करने का निर्णय लिया है । इन बाजारों में डिजिटल एवं ऑनलाईन मार्केटिंग ई–नाम से जुड़ाव कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, ट्रेडिंग प्लेटफार्म तथा किसानों और व्यापारियों के लिए पानी, सड़क, प्रकाश, शौचालय और सुरक्षा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले और दूसरे चरण में कुल 21 बाजार प्रांगणों में कार्य तेजी से चल रही है जिसके लिए 12 अरब 79 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है । मोहनिया, दाउदनगर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और वैशाली में कार्य पूरा हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं । शेष बाजार प्रांगणों में कार्य शीघ्र पूर्ण किये जायेंगे । साथ–ही–साथ तीसरे चरण में सरकार 10 और बाजारों के विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है । इसके अतिरिक्त सरकार गांव और अनुमंडल स्तर पर ग्रामीण हाट, ग्रामीण मंडी और ग्रामीण बाजारों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण करने पर भी कार्य कर रही है ।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत जी–राम जी की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हाट, बाजारों के निर्माण से किसानों को अपने क्षेत्र में ही बाजार की सुविधा मिलेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि यह प्रयास किसानों की आय वृद्धि, पारदर्शी बाजार व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है । बिहार सरकार किसानों के साथ, उनकी उपज को सम्मानजनक मूल्य दिलाने के लिए हमारी की प्राथमिकता है । माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी ने फुलवारीशरीफ के हिन्दुनी में थाना संख्या–37, खाता संख्या–158, खेसरा संख्या–853 में जिस तीन एकड़ 35 डिसमिल भूमि पर मंडी निर्माण हेतु प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया है, अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त जमीन पर सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तथा शेष भाग में 20 से 25 फीट गहरी तलाब है उसमें स्थानीय लोग छठ के रूप में उपयोग करते हैं । उक्त भूमि जल स्रोत एवं जल–जीवन–हरियाली से संबंधित है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेशिफिक पूछा है और इन्होंने जवाब भी दिया है । ये तो पूरा बिहार घूमा रहे थे, हम कह रहे हैं कि फुलवारी और पुनपुन जहां के किसान, 20 हजार से भी ज्यादा रजिस्टर्ड किसान जिनके लिए कोई मंडी नहीं है और ये कह रहे हैं कि मुसल्लहपुर में जाकर करें और उसका ये आधुनिकीकरण कर रहे हैं, आधुनिकीकरण करें लेकिन वे किसान वहां कैसे जा पायेंगे, उनकी लागत भी बढ़ेगी और उनकी दूरी भी बढ़ेगी तथा नो एंट्री है तो फिर वे क्या चाहते हैं ? मंत्री जी कह रहे हैं कि हिन्दुनी में ऐसा–ऐसा है, सूर्य मंदिर है, ठीक है तो अगल–बगल कहीं पर वे बाजार बनाने का विचार रखते हैं ? इन्होंने पहले ही कह दिया कि बनाने का कोई विचार नहीं है जब विचार ही नहीं है तो फिर वहां के किसान को आप मरने पर और बिचौलियों की चांदी करने के लिए छोड़ दिये हैं क्या ? तो मेरा यह कहना है कि फुलवारी या पुनपुन में आप मंडी बनाना चाहते हैं या नहीं ? स्पेशिफिक बात है, स्पेशिफिक जवाब दीजिये।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैंने लगातार किया है लोकसभा के अंतर्गत । उनकी भवना से मैं बिल्कुल सहमत हूँ मगर हमने बताया कि पूरे बिहार, हम तो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार किसी प्रखंड तक सीमित नहीं हैं । हमने बिहार में, हमारी सरकार की क्या योजना है उसके विषय में हमने जानकारी दी कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए किस तरह से मार्केट उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं तो इनको अगर लगता है कि फुलवारीशरीफ से पूरा बिहार है तो मुझे कुछ नहीं कहना है । पुनपुन प्रखंड के जाहिदपुर मंडी को ग्रामीण हाट के विकास का दर्जा दिया जा रहा है, वह इनके क्षेत्र में ही है, मैं उस क्षेत्र को जानता हूँ तो हर जगह मंडी की उपलब्धता हो जाय ऐसा संभव नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, केन्द्र सरकार की एक अच्छी योजना आयी है जी–राम जी, हमारा सुझाव होगा कि उसमें शामिल करते हुए और यदि वहां पर निर्माण कराया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा । माननीय मंत्री जी, जी–राम जी योजना की आपने जो चर्चा की है जिसे भारत सरकार ने अभी लायी है किसानों की सुविधा के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण हाट बनाने की योजना है ।

टर्न–5 / अंजली / 05.02.2026

श्री रामकृपाल यादव, मंत्री : आगे सरकार की जो नीति है उसके विषय में भी मैंने कहा, आगे विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं॰–114, श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र सं॰–143, तेघड़ा)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 280 योजना है, जिसमें 246 योजना का संचालन PHED द्वारा किया जाता है । विद्युत विपत्र एवं पंप चालकों के पारिश्रमिक भुगतान के पश्चात् ही संबंधित संवेदक / एजेंसी को भुगतान किया जाता है। शेष 34 योजना PRD द्वारा PHED को हस्तांतरित हैं, जिसके पम्प चालक के मानदेय भुगतान एवं विद्युत विपत्र का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। PRD द्वारा हस्तांतरित योजनाएं जो पम्प चालक के मानदेय भुगतान एवं विद्युत विपत्र बकाया रहने के कारण बाधित होती है उसे अविलंब संज्ञान में लेकर पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए पुनः जलापूर्ति बहाल कर दी जाती है । वर्तमान में सभी योजनाओं से नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, उत्तर मिला है लेकिन हमने जो प्रश्न में पूछा है उसका जवाब इसमें नहीं है, आधा–अधूरा उत्तर दिया गया है । हमने स्पष्ट पूछा है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में 280 नल–जल में से अधिकांश रख–रखाव एवं ऑपरेटर को मानदेय राशि के भुगतान नहीं होने के कारण बंद पड़ा हुआ है । रख–रखाव के विषय पर कोई उत्तर नहीं है और जहां तक ऑपरेटर के मानदेय की राशि के

भुगतान के सवाल पर इन्होंने जो कहा है, तो उसमें माननीय मंत्री जी से हम यह पूछना चाहते हैं कि पंप चालकों को पारिश्रमिक एवं विद्युत विपत्र के भुगतान की क्या यह एकमुश्त राशि दी जाती है या इसे मासिक स्तर पर दिया जाता है, माननीय मंत्री जी पहले यह बताएं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक । बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र में कुल 280 योजना है, जिसका इन्होंने जिक्र किया है । अध्यक्ष महोदय, उसमें 246 योजना का संचालन पी.एच.ई.डी. द्वारा किया जाता है । विद्युत विपत्र एवं पंप चालकों के पारिश्रमिक भुगतान के पश्चात् ही संबंधित संबंधित संवेदक/एजेंसी को भुगतान किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, शेष 34 योजना PRD द्वारा PHED को हस्तांतरित हैं, जिसके पम्प चालक के मानदेय भुगतान एवं विद्युत विपत्र का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, यह पूरे बिहार का मामला है और इसके लिए हमारी पंचायती राज मंत्री जी से बात भी हुई है कि सभी जगह पंप ऑपरेटर का जो मामला आ रहा है, इसके लिए हमलोग बात कर रहे हैं और माननीय सदस्य की चिंता जाहिर है, हमलोग इस पर बात कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा । साथ ही, अध्यक्ष महोदय, पी0आर0डी0 द्वारा जो संचालित योजना है उसके पंप चालक के मानदेय भुगतान एवं विद्युत विपत्र बकाया रहने के कारण जो बाधित हो रही है उसे अविलंब संज्ञान में लेकर पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए पुनः जलापूर्ति योजना बहाल कर दी जाएगी और वर्तमान में सभी योजनाओं के नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है ।

श्री रजनीश कुमार : सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि निष्कर्ष निकालकर पूरे बिहार में यह समस्या है, इसको किया जाएगा लेकिन...

अध्यक्ष : आप विधान सभा में है, विधान परिषद में नहीं हैं । सभापति महोदय नहीं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री रजनीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मत्री जी ने कहा कि पंप चालकों के पारिश्रमिक भुगतान के पश्चात् ही संबंधित संवेदक और एजेंसी का भुगतान किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि पंप चालक का पारिश्रमिक और विद्युत विपत्र का कोई भुगतान लंबित नहीं है और फिर इन्होंने कहा कि हम इसकी समीक्षा करवाकर इसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आधे से अधिक नल–जल योजना पूर्ण या आंशिक रूप से, मैं फिर कह रहा हूं कि उसमें रख–रखाव के कारण, कहीं पाइप टूट गया है, कहीं बंद पड़ा हुआ है, कहीं विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं हो रहा है, कहीं ऑपरेटर को पैसा नहीं मिल रहा है, इसके कारण अध्यक्ष महोदय, पूरा आधे से अधिक बंद है और अंत में इनका जो उत्तर है कि वर्तमान में सभी योजनाओं को नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है, यह पूरी तरह से सदन को दिग्भ्रमित करने वाला उत्तर है । ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई पर माननीय मंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि

यह माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, पेयजल से जुड़ी हुई समस्या है, अभी कुछ देर पहले सदन में यह विषय आया भी था और मैं यह कह रहा हूं कि इन दो कारणों से मुख्यतः बंद है, एक तो रख–रखाव का विषय है, माननीय मंत्री जी के द्वारा इस पर कोई उत्तर नहीं दिया गया है और जो भुगतान लंबित है यहां तक कि विद्युत विपत्र का भुगतान भी लंबित है, ऑपरेटर का भुगतान लंबित है और यह कमोबेश ठीक कहा कि शायद बिहार में, लेकिन मैं तो अपने विधान सभा क्षेत्र में पूरी समीक्षा करके कह रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, इसको माननीय मंत्री जी पूरी तत्परता के साथ लें और हमारे क्षेत्र में तो कम से कम जल्दी चालू करवा दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो कहा गया है हम बताना चाहेंगे कि हमने पहले ही कहा है कि इसमें दोनों विभागों के द्वारा पी.एच.ई.डी. और पंचायती राज के द्वारा जितने भी अनुरक्षक हैं, वह पहले पंचायती राज के जिम्मे था और उसका मेंटेनेंस भी पंचायती राज विभाग ही कर रही है तो जहां भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, हमने इसको पहले भी जवाब में दिया है कि हमलोग इसको अविलंब कर लेते हैं और इसकी समीक्षा करके बहुत जल्द इसको करवाने का काम करेंगे ।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, यह पंचायती राज विभाग का सिर्फ विषय नहीं है, यह उत्तर में है कि 280 योजना में 246 योजना इन्हीं का है, पी.एच.ई.डी. का ही है, मात्र 34 योजना पंचायती राज विभाग का है इसलिए इसका उत्तर पंचायती राज विभाग के माथे पर नहीं मढ़ा जा सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त दिया है कि समीक्षा करने के बाद संबंधित विभागों से राय करके निश्चित तौर पर बकाया का भुगतान, बिजली के बिल का भुगतान और मेंटेनेंस अच्छा हो, यह बेगूसराय का मामला है ।

माननीय सदस्य, श्री संदीप सौरभ । संदीप सौरभ जी ।

(व्यवधान)

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विषय सरकार को रेखांकित कराने के लिए...

अध्यक्ष : जरा सा प्लीज, आगे बढ़ गये हैं । विषय आ गया है । आपको अलग से समय देंगे । संदीप सौरभ जी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–115, श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र सं॰–190, पालीगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । विभागीय संकल्प संख्या–1239 दिनांक–13.04.2018 द्वारा सहकारिता विभाग अन्तर्गत बिहार के सभी 101 अनुमंडलों (पालीगंज सहित) में सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का पद पुनर्गठित/सृजित किया गया । इनमें से 54 सहायक निबंधक, स0स0 कार्यालय पूर्व से कार्यशील हैं । पालीगंज सहित नवसृजित कुल 47 अनुमंडलों में सहायक निबंधक, स0स0 के कार्यालय हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से निकासी एवं

व्ययन का प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ये कार्यालय वर्तमान में कार्यशील नहीं हो पाये हैं।

उक्त अनुमंडलों में कार्यालय स्थापित करने हेतु मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त इनके अधीनस्थ विभिन्न प्रकार के संवर्गो में पद सृजित करते हुए विभागीय पत्रांक–6556 दिनांक–31.12.2025 द्वारा कार्यालय के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके आलोक में वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–594 दिनांक–15.01.2026 द्वारा महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना से इन नवसृजित कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन का प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । सहकारिता विभाग से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु पालीगंज, दुल्हिनबाजार एवं बिक्रम सहित सभी प्रखंडों में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद सृजित एवं कार्यरत हैं । उक्त सभी प्रखंड ARCS दानापुर के अधीन आते हैं ।

3. उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो कुछ देर पहले ही मिला है । यह बड़ा गंभीर सवाल है । दानापुर अनुमंडल में पहले पालीगंज अनुमंडल था, अलग हो गया। हमने बहुत–सा सीधा सा सवाल किया था कि सहकारिता विभाग जो है ए0आर0सी0एस0 यह अब तक अनुमंडल पालीगंज में क्यों शिफ्ट नहीं किया गया है, इसको शिफ्ट करना चाहिए था । सरकार ने सहायक निबंधक पद के लिए स्वीकृति दी थी दिनांक–13.04.2018 को कि वहां पदाधिकारी बैठाएं जाएंगे लेकिन अभी तक गोल–गोल पूरा जवाब आया है और इसके चलते पालीगंज अनुमंडल के जितने सारे गांव हैं, वहां के किसानों को सहकारिता से संबंधित किसी भी काम के लिए 50–60 किलोमीटर की दूरी तय करके उनको दानापुर आना पड़ता है, अगर पदाधिकारी वहां नहीं मिले तो फिर वापस जाइए और फिर आइए, यह बहुत गंभीर मामला हो चुका है लेकिन जवाब बहुत स्पष्ट नहीं है । हम चाहेंगे कि एक बार माननीय मंत्री जी इस पर ठोस जवाब दे दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, जवाब स्पष्ट है और उनको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा दे रहा हूं और इनको...

(व्यवधान)

नहीं–नहीं, एक मिनट । सुन लीजिए । माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

श्री संदीप सौरभ : अभी तक आप अनुरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्पष्ट जवाब है । अभी तक आप अनुरोध ही कर रहे हैं न जवाब में ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य, सुनने की क्षमता रखिए न । आप सवाल किए हैं तो जवाब सुनिए । विभागीय संकल्प संख्या–1239 दिनांक–13.04.2018 द्वारा सहकारिता विभाग अन्तर्गत बिहार के सभी 101 अनुमंडलों उसमें पालीगंज सहित में सहायक निबंधक, सहयोग समिति का पद पुनर्गठित किया गया है ।

(व्यवधान)

एक मिनट, सुन लीजिए भाई । आप पूरी बात सुनिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप बोलिए । आप बोलते रहिए ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : जिनमें से 54 सहायक निबंधक, सहयोग समितियां कार्यालय पूर्व से कार्यशील हैं । पालीगंज सहित नवसृजित कुल 47 अनुमंडलों में सहायक निबंधक, सहयोग समितियां के कार्यालय हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से निकासी एवं व्ययन का प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ये कार्यालय वर्तमान में कार्यशील नहीं हो पाये हैं ।

उक्त अनुमंडलों में कार्यालय स्थापित करने हेतु मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त इनके अधीनस्थ विभिन्न प्रकार के संवर्गो में पद सृजित करते हुए विभागीय पत्रांक–6556, दिनांक–31.12.2025 द्वारा कार्यालय के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके आलोक में वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–594 दिनांक–15.01.2026 द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदार), बिहार, पटना से इन नवसृजित कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन का प्राधिकार पत्र जैसे प्राप्त होगा वैसे वहां कार्यालय खोल दिया जाएगा । अब इसके बाद आपको और कैसा जवाब चाहिए माननीय सदस्य । आप सबलोगों को तो बिना नियम–कानून से काम करने की आदत है, तो यह सरकार बिना नियम–कानून से काम तो करेगी नहीं, जो नियम कानून होगा उसी हिसाब से होगा ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, यह क्या जवाब दिया जा रहा है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट, सुन लीजिए ।

टर्न–6 / पुलकित / 05.02.2026

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किसी तरह से न तो कम जानकार हैं किसी से और न इनकी सूचना गलत है । माननीय मंत्री जी को इन सवालों का जवाब संजीदगी के साथ रखना चाहिए और ये माननीय विधायक की भी इज्जत और मर्यादा का सवाल है । अभी कई प्रश्न किए गए, सरकारी उत्तर जो आता है वो गलत भी आ रहा है, फिर भी उस पर स्टैंड लेना गलत है। माननीय सदस्यों की जो सूचना है या जानकारी है उसको संज्ञान में लेना चाहिए। वेरीफाई कर लीजिए, यदि गलत हो तो उस पर एक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि गलत नहीं हो माननीय सदस्य की सूचना तो उसके आधार पर जो पदाधिकारी गलत जवाब दे रहे हैं, उस पर संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई की जाए ।

अध्यक्ष : जरूर सरकार कार्रवाई करेगी ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, हम तो बहुत सामान्य सी बात कह रहे थे। पद सृजन 2018 में होता है और आप कह रहे हैं कि जब हमने विधानसभा के अंदर प्रश्न लिखकर के डाल दिया, जब विभाग को सूचना मिली उसके बाद 15.01.2026 को आप अनुरोध

कर रहे हैं कि हमें निकासी और व्ययन का प्राधिकार दिया जाए । महोदय, यह बात को गोल–गोल घुमाना ही तो हुआ । जब 2018 से यह स्वीकृत पद था तो आपने क्यों नहीं पद भरा ? यह ठोस बात आपको कहनी चाहिए थी । मंत्री जी जवाब देने के बजाए धमकी दे रहे हैं, इस भाषा में जवाब दिया जाता है ? इस भाषा में क्या मंत्री महोदय जवाब देंगे, यह कोई भाषा है क्या ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ये गोल–गोल जवाब दे रहे हैं ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, धमकी तो हम लोग नहीं दे सकते हैं।

श्री संदीप सौरभ : आप स्पष्ट बताइये कि कब तक हो जाएगा...

(व्यवधान)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : धमकी देने का तो इधर से कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जो जवाब है, वह जवाब स्पष्ट है।

श्री संदीप सौरभ : कब तक हो जाएगा, आप सिर्फ यह बताइये ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य, बिना महालेखाकार के अनुमति के नहीं हो सकता है । जैसे महालेखाकार की अनुमति आएगी, निकासी एवं व्ययन प्राधिकार का पत्र जैसे प्राप्त होगा, आपको हम कहां कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन गलत किए हैं ? आपका क्वेश्चन जायज है, सही है । लेकिन जब तक महालेखाकार....

(व्यवधान)

हम कहां कह रहे हैं कि जवाब गलत है । आन्सर सही–सही लिखा हुआ है । जैसे मिलेगा वैसे कार्यालय खोल दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रयास कीजिए, जल्द हो जाए ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–116, श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र सं0–229, बोधगया (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

नगर परिषद्, बोधगया क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या–26, मुहल्ला–पुरानी तारीडीह में देवी स्थान (पिपरपांती) से राजु ठाकुर के घर होते हुए वाटपा थाई मंदिर (सिद्धी पासवान के घर) तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण का प्राक्कलन तैयार करने का निर्णय नगर परिषद् द्वारा लिया गया है।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हमने यह सिर्फ आग्रह किया था कि बोधगया एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल है । जिस सड़क का हमने आग्रह किया, उसमें थाईलैंड, श्रीलंका ऐसे देशों के कम से कम पांच से ज्यादा मंदिर हैं। माननीय मुख्यमंत्री साल में कम से कम चार बार बोधगया जाते हैं। बुद्ध मंदिर की दीवार के पीछे यह गांव बसा हुआ है । इसके पीछे थाईलैंड का बहुत बड़ा मंदिर है और हमने इसलिए कहा कि विदेशों में, जो बौद्ध कंट्री के लोग आते हैं विदेश से तो विदेशों में जो आपका मैसेज जा रहा है कि विदेशी लोग जो हैं अपना जूता हाथ में लेकर के बरसात में यहां से पार होते हैं । इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया तो इन्होंने लिखा है कि प्राक्कलन तैयार करने का निर्णय नगर

परिषद द्वारा लिया गया है । मंदिर बने हुए महोदय बीसों साल हो गए । आप भी जाते रहते हैं, हम सिर्फ निवेदन करना चाहते हैं कि बुद्ध मंदिर अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, इसके पीछे यह गांव बसा हुआ है, कम से कम छह से सात विदेशी मंदिर हैं, इस सड़क को हम सिर्फ बना देने की नम्र निवेदन आपसे कर रहे हैं । अगर आपकी अनुमति होगी, आप कहेंगे हम अपने लेटर हेड पर आपको लिखकर के मैं गुजारिश कर सकता हूं । चूंकि आपकी इसमें बदनामी हो रही है, विदेशी लोग जाते हैं इसलिए मैंने आग्रह किया ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद बोधगया में वार्ड 26 में सड़क नाला बनाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बोधगया द्वारा पत्रांक 93, दिनांक 24.01.2026 द्वारा सर्वेश नारायण शर्मा, कनीय अभियंता से उक्त स्थल का प्राक्कलन तैयार करने हेतु निर्देश दे दिया गया है । महोदय, उम्मीद है कि जल्द से जल्द बनने के लिए विभाग को निर्देशित किया जाएगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सर्वजीत जी, आपको जानकारी भी होगी । सर्वजीत जी, जैसा आपको जानकारी होगी कि केंद्र सरकार के प्रयास से उज्जैन महाकाल, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर गयाजी, बोधगया कॉरिडोर का निर्माण कराने का निर्णय भी हुआ है नंबर एक । उस बैठक में आप स्वयं सम्मिलित भी थे । उसका जो पी0पी0टी0 प्रस्तुत किया जा रहा था और आप स्वयं मतलब 29 तारीख को शामिल थे, हमें भी आमंत्रित किया गया था । हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में बिहार का जो इम्पोर्टेन्ट हमारा स्थल बोधगया जो है, जहां बौद्ध धर्मावलंबी पूरे विश्व से आते हैं और हिन्दू धर्मावलंबी गया जी में आते हैं । दोनों के लिए भारत सरकार ने एक कंसल्टेंट बहाल कर दिया है, योजना का डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है । हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में उज्जैन महाकाल और काशी विश्वनाथ की तरह गयाजी, बोधगया बदल जाएगा।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कि भारत सरकार से बोधगया कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है ।

अध्यक्ष : उसमें सड़क भी शामिल है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं मीटिंग में था ।

अध्यक्ष : हां, आप उस मीटिंग में थे ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, कॉरिडोर कहां पर बनना है यह भी मैंने मीटिंग में समझ लिया । महोदय, यह मंदिर के पीछे का मामला है ।

अध्यक्ष : शामिल कर लिया जाएगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, आप एक बार जाकर के देख लीजिए ।

अध्यक्ष : जरूर ।

श्री कुमार सर्वजीत : आप गया जी से आते हैं, आप एक बार चल कर देख लीजिए कि दीप तले अंधेरा जो होता है न महोदय, इतना बड़ा मंदिर विश्व विख्यात है, उसके पीछे इतना नरक है, इसलिए मैंने आग्रह किया ।

अध्यक्ष : सभी मंदिरों को शामिल किया जाएगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : कॉरिडोर के बारे में तो महोदय मैं जानता ही हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कॉरिडोर में सारे मंदिरों को शामिल किये जा रहे हैं । उसमें बोधगया का भी है ।

श्री कुमार सर्वजीत : हुजूर, हमने कहा कि कॉरिडोर के बारे में तो हम जानते ही हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू ।

(व्यवधान)

आप ही के माननीय का प्रश्न है ।

श्री भाई बिरेंद्र : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो एल0ई0डी0 डिसप्ले लगी हुई हैं उसमें सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को ही दिखाया जाता है । विपक्ष के माननीय सदस्यों को नहीं दिखाया जाता है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी भी है और यह खुद वहां से प्रतिनिधित्व भी कई बार किए हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं । महोदय, आज बोधगया के अंदर, हम अभी तुरंत वहां गये थे, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद भी लगाए, कई समस्याएं भी आई और संजोग से हमारे पास नगर विकास मंत्रालय भी है । महोदय, माननीय मंत्री जी पुरानी तारीडीह में देवी स्थान राजू ठाकुर के घर से होते हुए वाटपा थाई मंदिर (सिद्ध पासवान के घर) तक पी0सी0सी0 पथ नाला निर्माण का जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं । महोदय, जब इसको स्वीकार कर लिया गया है, छह माह के अंदर काम कर दिया जाएगा । सरकार सजगता के साथ पर्यटक स्थलों के विकास के लिए संकल्पित है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य धन्यवाद दे दीजिए माननीय मंत्री जी को ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से हम चैम्बर में जाकर के बोधगया का तिलकुट खिला देंगे । धन्यवाद महोदय ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–117, श्री रणविजय साहू (क्षेत्र सं0–135, मोरवा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

उक्त सड़क एवं नाला निर्माण के लिए सामान्य बोर्ड के दिनांक–22.12.2025 के प्रस्ताव सं0–6 (v एवं vii) द्वारा सड़क एवं नाला निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ, उत्तर प्राप्त है । लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं है । महोदय, हमारे क्षेत्र की यह महत्वपूर्ण सड़क है और इस सड़क की लम्बाई 5 किलोमीटर है। यह सड़क जो है वह आर0डब्ल्यू0डी0 की है । महोदय हम मंत्री जी को सिर्फ इतना ही आग्रह किए थे कि यह सड़क जो शहरी इलाका है, जहां स्कूल भी है, मस्जिद भी है, और वहां हमेशा पानी लगा रहता है, कीचड़ लगा रहता है तो माननीय मंत्री जी इस सड़क को आर0डब्ल्यू0डी0 से अपने विभाग में ट्रांसफर करके कब तक बनाना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न किए हैं वह सामान्य बोर्ड के दिनांक–22.12.2025 के प्रस्ताव सं0–6 (v एवं vii) द्वारा सड़क

एवं नाला निर्माण करने का निर्णय लिया गया है । इस पर विभाग गंभीरता के साथ स्वीकार करते हुए काम करेगी ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, लगातार हम कई बार सदन में इस सवाल को लाए हैं । पांच वर्षों में मैंने इस सड़क को, पटोरी का नगर परिषद को गठन हुए लगभग पांच वर्ष हो गये । लेकिन सड़क नहीं बनने के कारण वहां पूरी तरह से लोगों को खासकर के जो राहगीर हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, मरीज हैं, उनको काफी कठिनाई होती है । हम जानना चाहते हैं मंत्री जी समय सीमा सुनिश्चित कर दें, जिस प्रकार से माननीय सर्वजीत जी को सर सुनिश्चित कर दिए छह माह में, हमको भी सुनिश्चित कर दें ताकि हमारे जनता को लगे कि निश्चित रूप से यह काम होने वाला है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि एक विभाग से दूसरे विभाग के अंदर लेना कई प्रक्रियाओं से गुजरता है । प्रक्रिया पूरा होने पर काम जल्द से जल्द होगा ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : बात आ गयी है, अब बैठ जाएं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–118, श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र सं0–217, घोसी)</u>
(लिखित उत्तर)

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

1. वस्तुस्थिति यह है कि डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के अधिसूचना सं०–967, दिनांक–15.05.2023 द्वारा बाढ़/आपदा राहत हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के अनुसार बाढ़ प्रभावित घोषित जिलों के मछुआरों/मत्स्य कृषकों को क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है।

2. उक्त प्रावधान के आलोक में संबंधित जिला के मत्स्य कृषकों के परिसंपत्तियों का संधारण जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उक्त संधारित परिसंपत्तियों की सूची जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से अनुमोदित है।

3. आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा वर्श 2025 में जहानाबाद जिला को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया है, जिस कारण मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के अनुसार मत्स्य कृषकों को क्षतिपूर्ति की राशि अनुमान्य नहीं है।

2– उक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री रितुराज कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है मगर उसके तीसरे खंड में लिखा हुआ है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जहानाबाद जिले को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया था, जिस कारण से मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार मत्स्य कृषकों की क्षतिपूर्ति की राशि अनुमान्य नहीं है। महोदय, आपको भी विगत

है कि पिछले वर्ष फल्गु नदी में बाढ़ आई थी और मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो प्रखंड उससे बुरी तरह प्रभावित हुए थे। अगर बाढ़ प्रभावित उसको नहीं भी घोषित किया गया है, तो किसी मानक के अनुसार उनकी क्षतिपूर्ति की जाए क्योंकि उस दो प्रखंड में लगभग 10 करोड़ का नुकसान हुआ है मछली पालकों को । माननीय मंत्री जी इसके ऊपर जवाब दे दें ।

टर्न–7 / हेमन्त / 05.02.2026

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के अधिसूचना सं0–967, दिनांक 15.05.2023 द्वारा बाढ़ / आपदा राहत हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ प्रभावित घोषित जिलों के मछुआरों / मत्स्य कृषकों को क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधान के आलोक में संबंधित जिला के मत्स्य कृषकों के परिसंपत्तियों का संधारण जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उक्त संधारित परिसंपत्तियों की सूची जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से अनुमोदित है।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा वर्ष 2025 में जहानाबाद जिला को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया है, जिस कारण मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार मत्स्य कृषकों को क्षतिपूर्ति की राशि अनुमान्य नहीं है।

उक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री रितुराज कुमार : महोदय, बाढ़ तो आयी थी। दो प्रखंडों में उसकी क्षति भी हुई है। तो क्षतिपूर्ति तो करवाना ही होगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, पुनः दिखवा लीजिए एक बार।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : जी।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें।

अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ली जायेंगी।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 05 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं–

श्री अख्तरूल ईमान, स0वि0स0, श्री गुलाम सरवर, स0वि0स0, मोहम्मद सरवर आलम, स0वि0स0, मोहम्मद मुर्शिद आलम, स0वि0स0 एवं श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0।

आज दिनांक 05 फरवरी, 2026 को सदन में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद एवं सरकार का उत्तर निर्धारित है।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 6 (3) एवं 47 (2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन की सूचना को अमान्य किया जाता है।

श्री अख्तरूल ईमान : सर, जरा पढ़ने दिया जाय। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष : ठीक है।

श्री अख्तरूल ईमान : सर, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मधेपुरा में हीना खातून का सामूहिक बलात्कार कर हत्या, पटना में NEET की छात्रा के साथ बलात्कार एवं हत्या, नवादा में कपड़ा व्यवसायी अतहर हुसैन की भीड़तंत्र द्वारा हत्या एवं सुपौल के नुरशेद आलम की भीड़तंत्र द्वारा जानलेवा हमला, पूर्णिया के युवा व्यवसायी सूरज बिहारी को दिनदहाड़े गोली मारना, बेगूसराय में कपड़ा व्यवसायी शहजादे की रंगदारी न देने पर हत्या, ये सभी ताजा उदाहरण हैं। इन लगातार आपराधिक घटनाओं के कारण जनता में असुरक्षा की भावना है और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय काफी खौफ में है।

अतः में उपरोक्त विषय पर विचार–विमर्श हेतु सदन के कार्य स्थगन का प्रस्ताव देता हूं।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे।

श्री अख्तरूल ईमान : सर, बहुत ही गंभीर मामला है। इसको जरा दो–चार शब्दों में करवा दीजिए।

अध्यक्ष : आपने अपनी बात को बोलकर रिकॉर्ड कराया है। सरकार ने सुना है आपकी बातों को, सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी।

माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल लिये जायेंगे। माननीय मिथिलेश तिवारी जी कुछ कहना चाहते थे, बताइये। उस समय कुछ कहना चाह रहे थे ?

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाह रहे थे कि यह सरकार के ध्यान में लाना इसलिए जरूरी है कि नल–जल की यह जो योजना पूरे बिहार में चल रही है उसमें सबसे बड़ा गैप यह है कि पिछली बार जब यह योजना आयी थी और उस समय जो वार्ड सदस्य जीते थे, उन्होंने अपनी जमीन पर नल–जल की टंकी लगा दी उसके बाद दूसरे चुनाव में वह हार गये, दूसरा कोई जीत गया और जो वह अपनी जमीन पर लगाये थे, तो वह कहते हैं कि पैसा हमको मिलना चाहिए और जो जीता है, उसको वहां जाने नहीं देता है। अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी समस्या है, हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि इसके लिए कोई नीति जरूर बननी चाहिए जिससे इसका समाधान हो सके। धन्यवाद।

शून्यकाल

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के कोढ़ा चौक से सेमापुर जाने वाली सड़क आर0सी0डी0 के अधीन है। सड़क चौड़ीकरण हेतु मुख्य अभियंता के द्वारा तकनीकी स्वीकृति 05 जून, 2025 को मिलने के बावजूद 08 माह से अभियंता प्रमुख के यहां पर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित है। उक्त सड़क चौड़ीकरण हेतु सरकार से मांग करती हूं।

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रकृति में नवाचार से जुड़े अत्यंत लोकप्रिय आदिवासी भाइयों के 'सोहराय' पर्व के अवसर पर साल के जनवरी महीने में दो दिनों का सरकारी अवकाश घोषित किये जाने की मांग सरकार से करती हूं।

श्री नंद किशोर राम : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंडों रामनगर एवं गौनाहा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यह क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, अतः जनहित में रामनगर में डिग्री कॉलेज बनाने की मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा अनुमंडल अंतर्गत भिड़हा से कोलहट्टा सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मिल गयी थी। लेकिन अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। उद्घाटन के बावजूद डेढ़ साल से लंबित है। भिड़हा से कोलहट्टा सड़क कार्य प्रारंभ करने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल में ब्लड बैंक और वेंटिलेटर युक्त आई0सी0यू0 का अभाव है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण गंभीर मरीजों को मोतिहारी या बाहर रेफर करना पड़ता है जिससे इलाज में देरी होती है। जनहित में सरकार से यहां आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

श्री अभिषेक रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया GMCH में दिनांक 21 जनवरी, 2026 को सुशीला देवी की इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हो गयी तथा परिजनों के साथ मारपीट की गयी, नगर थाना कांड संख्या 46/26 दर्ज है। दोषी डॉक्टरों और कर्मियों की गिरफ्तारी की मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड केवटी एवं सिंहवाड़ा के अधिकांश अपग्रेडेड 10+2 विद्यालय का अपना भवन नहीं रहने के कारण छात्रों का वर्ग संचालन दो शिफ्ट में किया जाता है जिससे छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छात्रहित में भवन बनाने की कृपा करें।

मोहम्मद मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड, मियांपुर ग्रामपंचायत अंतर्गत सालगोरी के निकट PMGSY पथ में वर्ष 2024 में आयी बाढ़ से पुल ध्वस्त हो गया है। पुल टूटने के कारण पंचायत दो भागों में बंटा हुआ है तथा आवागमन ठप है।

मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत बेलवा पंचायत (वार्ड–12) के चिलमारी नदी घाट पर पुल नहीं होने से हजारों की आबादी प्रभावित है। बरसात

के दिनों में आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है। जनहित में सरकार यहां अविलंब पुल निर्माण कराए। मैं इसकी मांग करता हूं।

श्री गुलाम सरवर : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला बायसी प्रखण्ड अन्तर्गत ताराबाटी पंचायत को अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय से नहीं जोड़ा गया है। जिसके कारण उक्त पंचायत स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आवागमन जैसी मूल सुविधाओं से वंचित है। उक्त पंचायत को अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने हेतु सड़क एवं पुल निर्माण की मांग करता हूं।

श्री भरत बिंद : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के भभुआ प्रखंड अन्तर्गत ग्राम मचियांव या तियरा घट के सामने दुर्गावती नदी पर पुल नहीं होने के कारण लगभग दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है।

अतः उक्त नदी पर पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट नगर पंचायत के डिहरी बिक्रमगंज से प्रखण्ड मुख्यालय (गोड़ारी), थाना, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, विद्युत कार्यालय सहित एस0एफ0सी0 गोदाम होते हुए नाद ग्राम तक जाने वाली सड़क को पक्कीकरण (पी0सी0सी0) कार्य कराने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं।

टर्न–8 / संगीता / 05.02.2026

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुलतानगंज को अनुमंडल एवं रतनगंज, करहरिया एवं अकबरनगर को प्रखंड बनाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से गोपालगंज जिलान्तर्गत माँझा प्रखण्ड में ड़ोमाहाता, छवही खास में कैबिनेट की स्वीकृति से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 4.63 एकड़ सरकारी जमीन हस्तांतरित होने के बावजूद शिक्षा और निबंधन विभाग द्वारा केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए पहल करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री शुभानंद मुकेश : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के न होने से वर्षों से सिजेरियन ऑपरेशन बंद है । इस कारण गरीब प्रसूताओं को निजी अस्पतालों या भागलपुर रेफर होना पड़ता है, जो अत्यंत कष्टदायक है ।

अतः जनहित में यहां अविलंब एनेस्थीसिया चिकित्सक की स्थायी नियुक्ति की मैं मांग करता हूं ।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला में रीगा चीनी मिल छोड़कर कोई भी दूसरा उद्योग नहीं है जिसके कारण लोगों को काम व रोजगार के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है ।

अतः सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड में चावल, मक्का, आलू आधारित उद्योग लगाने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड–विभूतिपुर, पंचायत–पतैलिया, दिव्यधाम से बेगूसराय जिला के प्रखंड–खोदावनपुर, पंचायत–मालपुर के मटिहानी गांव के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है ।

मैं, सरकार से उक्त स्थान पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर प्रखण्ड के दरियापुर में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के सुचारू पठन–पाठन हेतु अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण करने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री सुरेंद्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला के सेमरी रेफरल अस्पताल और सूर्या क्लीनिक बेतिया के देखरेख में बांध्या करण (नसबंदी) दिनांक–03.02.2026 को ऑपरेशन के दौरान आदिवासी महिला केवंती देवी की मौत हो गई, मैं सरकार से चिकित्सक एवं अस्पताल प्रबंधक पर कार्रवाई करते हुए मुआवजा एवं परिजन को नौकरी देने के लिए मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री रोमित कुमार जी, आपका शब्द ज्यादा आ गया है, नियम है 50 शब्द तो भविष्य में उसी अनुकूल आप डालेंगे । रोमित कुमार जी बोलिए ।

श्री रोमित कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बथानी, खिजरसराय एवं अतरी प्रखंड के पंचायत जैसे– होरमा, शिसवर, गेहलौर, बथानी जैसे अनेक पंचायतों में जल–नल योजना/पेयजल आपूर्ति की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है । कई स्थानों पर अब तक नल–जल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायी है, वहीं कुछ जगहों पर कार्य अपूर्ण/लंबित रहने के कारण ग्रामीणों को भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है । सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि अतरी विधान सभा क्षेत्र के प्रभावित पंचायतों एवं ग्रामों में जल–नल योजना का त्वरित सर्वे कराकर, कार्यादेश निर्गत करते हुए, पाइपलाइन/टंकी/नल कनेक्शन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए ।

श्री सुजीत पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर विधानसभा क्षेत्र के राजनगर एवं अंधराठाढ़ी क्षेत्र नगर पंचायत गठन के सभी मानकों को पूर्ण करते हैं, फिर भी अब तक नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इन्हें नगर पंचायत घोषित नहीं किया गया है ।

अतः सरकार से मांग करता हूं कि नगर पंचायत गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें ।

श्री जनक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारण जिला अंतर्गत हमारे तरैंया विधानसभा के प्रखंड पानापुर के भोरहां डाकबंगला के पास गंडक नदी पर परिवहन की सुविधा, दूरी की कमी, फसल की सुरक्षा, आर्थिक मजबूती, कृषि आधुनिकीकरण एवं कनेक्टिविटी हेतु किसानों के हित में दियरा जाने के लिए पीपा पुल का निर्माण करावें ।

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया विधान सभा के ईस्ट ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं होने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु काफी दूर जाना पड़ता है । जबकि केजीपी +2 उच्च विद्यालय भोगा भटगामा में सात एकड़ भूमि उपलब्ध है ।

अतः मैं उक्त विद्यालय में सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने की मांग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिलांतर्गत पालीगंज प्रखंड के पालीगंज बाजार में भीषण सड़क जाम और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है । बाजार में बड़ी गाड़ियों के प्रवेश से घंटों तक सड़क अवरूद्ध रहती है ।

अतः इसके समाधान हेतु पालीगंज के धरहरा से फतेहपुर तक बाइपास सड़क का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, हीना खातुन, पति–स्व0 मो0 अताबुल, उम्र–30 वर्ष ग्राम–भैरूपति, थाना–मुरलीगंज (मधेपुरा) का 03.01.2026 को असामाजिक तत्वों ने अगवा कर दुष्कर्म किया फिर हत्या कर दी गयी । मृतका के 06 बच्चे अनाथ हो गये।

अनाथ बच्चों के लिए सरकारी तौर पर शिक्षा की व्यवस्था, 50 लाख रुपया मुआवजा एवं अपराधियों को कठोर सजा की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के नुआँव प्रखंड में सिसौढ़ा–मुखराँव पथ के गोरिया नदी पर संकीर्ण पुल रहने के कारण बरसात में पानी अवरूद्ध होता है । जिस कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से हजारों एकड़ धान की फसल क्षति होती है । उक्त जगह पर बड़ा पुल बनाने की मांग करता हूं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने पूर्वी चंपारण जिला के चकिया में चीनी मिल लगाकर इस इलाके कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की घोषणा की है । इस संदर्भ में कृषक हित में एक निश्चित समय सीमा के अंदर चीनी मिल लगाकर चालू करने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती अनीता : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के प्रखंड–पकरीबरावां में अंगीभूत स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं है । वहां के छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । पकरीबरावां में महाविद्यालय स्थापित करने हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है ।

अतः पकरीबरावां में अंगीभूत स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थापित करवाने की मांग करती हूं ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर विधान सभा में महिलाओं को सुरक्षित और सहज यात्रा को प्राथमिकता देने हेतु दरभंगा से अलीनगर, तारडीह एवं धनश्यामपुर प्रखण्ड तक महिला यात्रियों के लिए आधुनिक

सुविधाओं सहित पिंक बस सेवा का परिचालन की स्वीकृति हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार गोपालगंज जिला के डुमरिया घाट पर निर्मित नारायणी रिवर फ्रंट एवं निर्माणाधीन विद्युत शवदाह गृह की सुरक्षा हेतु लगभग एक हजार मीटर लम्बा प्रोटेक्शन वाल का निर्माण शीघ्र करावे ।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत कटिहार सीमा कुर्सेला से भाया–टोपड़ा मोहनपुर, लालगंज, विजयघाट, भागलपुर मधेपुरा सीमा तक सालों भर बहने वाली कोशी नदी में भयंकर बाढ़ से क्षेत्र के किसानों को कटाव के कारण विस्थापन एवं फसल व जानमाल की क्षति होती है ।

अतः वर्णित क्षेत्र के निवासियों के हित में रिंग बांध सुरक्षार्थ वोल्डर पीचींग, स्लूईश गेट निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहपुर विधान सभा अन्तर्गत खरीक प्रखंड के गोटखरीक ग्राम में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को आने–जाने के लिए रास्ता नहीं है । बच्चे–बच्चियों को दूसरे के जमीन पर पगडंडी से जाना पड़ता है ।

अतः रास्ता के लिए जमीन अधिग्रहण कर यथाशीघ्र सड़क बनवाने की मांग करता हूं ।

टर्न–9 / यानपति / 05.02.2026

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जायेंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

श्री श्याम रजक, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री श्याम रजक अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलांतर्गत फुलवारीशरीफ विधान सभा के फुलवारीशरीफ प्रखंड में गर्ल्स कॉलेज की आवश्यकता है, कॉलेज नहीं रहने से इंटर की पढ़ाई के बाद छात्राओं को शिक्षा के लिए पटना आना पड़ता है जिससे छात्राओं को आने जाने में काफी कठिनाई होती है । ऐसी स्थिति में बहुत सी छात्राएं उस शिक्षा से वंचित रह जाती हैं जो एक गंभीर समस्या है ।

अतएव फुलवारीशरीफ प्रखंड में गर्ल्स कॉलेज की स्थापना हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखंडों में जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है उन प्रखंडों

में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इस क्रम में विभागीय पत्रांक–40, दिनांक–14.01.2026 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों से भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है । यद्यपि फुलवारीशरीफ प्रखंड में संप्रति कोई अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं है तथापि इस प्रखंड में एल0पी0 शाही कॉलेज, फातिमा डिग्री कॉलेज, फुलवारीशरीफ एवं त्रिमूर्ति कॉलेज, इस्माइलपुर के रूप में तीन संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं जहां सह शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में फुलवारीशरीफ प्रखंड में महिला महाविद्यालय खोलने का तत्काल मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है । लेकिन चूंकि महोदय माननीय सदस्य ने इस बात को कहा है तो हमलोग इसपर निश्चित रूप से विचार करेंगे । गौरतलब यह भी है कि 213 प्रखंडों में जहां डिग्री कॉलेज नहीं है वहां हमलोग प्राथमिकता से डिग्री कॉलेज खोलने की, संचालन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस सत्र में और माननीय सदस्य का जो सुझाव है उसपर निश्चित रूप से हमलोग सकारात्मक रूप से विचार करेंगे लेकिन इसपर प्राथमिकता पहले होगी 213 की । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : धन्यवाद नहीं दीजिए, इतना अच्छा जवाब है ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो तीन महाविद्यालय का नाम लिया है वह बी0एड0 कॉलेज है और वहां सभी विषयों की पढ़ाई नहीं होती है और वह प्राइवेट स्कूल है इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर एक भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है, लोग वंचित रहते हैं और जमीन की उपलब्धता है । फुलवारी ब्लॉक के पास ही पीछे में सरकार की जमीन है, अगर सरकार प्राथमिकता के आधार पर लेती है तो बहुत अच्छा होगा । फुलवारी की बच्चियों को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जमीन तो हमने भी देखा है जहां का जिक्र कर रहे हैं माननीय सदस्य । निश्चित रूप से उनकी चिंता वाजिब है और 213 के बाद उसको हमलोग प्राथमिकता पर निश्चित रूप से ले लेंगे । वहां जरूरत है महोदय । धन्यवाद ।

श्री श्याम रजक : धन्यवाद ।

सर्वश्री राणा रणधीर, अनिल सिंह एवं अन्य पांच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राणा रणधीर जी अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, राज्य की अनेक छोटी एवं मौसमी नदियों जैसे फल्गु, पुनपुन, किऊल–हरोहर, बदुआ, चानन, धनौती, सकरी, बकरा, तिलावे, करमनाशा, पंचाने, दरबा, कछुआ नाला, चकनाहा तथा स्थानीय धाराएं वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सूख जाती हैं । इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर निरंतर चिंताजनक रूप से नीचे जा रहा है । नदियों पर वर्षाजल संचयन हेतु चेक डैम निर्माण, जल संरक्षण संरचनाएं एवं स्थायी उपाय नहीं किये गए हैं, जिससे बहुमूल्य वर्षाजल बिना उपयोग के बहकर नष्ट हो

जाता है । इसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है, जिन्हें सिंचाई के अभाव में फसल उत्पादन में कमी झेलनी पड़ती है । पशुपालकों को पशुओं के पेयजल में कठिनाई तथा आम नागरिकों को ग्रीष्म ऋतु में घरेलू जल संकट का सामना करना पड़ता है । यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्य भीषण जल संकट की चपेट में आ सकता है ।

अतः जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण एवं वर्षाजल संचयन सुनिश्चित करने के लिए बिहार की नदियों पर व्यापक स्तर पर चेक डैम एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा स्थापना दिवस के मौके पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी भी आ रहे हैं, माननीय उप सभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी का भी आगमन होगा और नेवा योजना के उद्घाटन के लिए माननीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय श्री किरण रिजिजू जी भी आ रहे हैं और उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, द्वैय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद रहेंगे । सबों से आग्रह है कि 07 फरवरी को होनेवाले बिहार विधान सभा स्थापना दिवस के मौके पर व्याख्यान में निश्चित तौर पर, यह कार्यक्रम तीन घंटे का है जो 10.30 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगा और 1.30 बजे अपराह्न में समाप्त हो जायेगा, सबों से आग्रह है कि निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहेंगे ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–10 / मुकुल / 05.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक– 3 फरवरी, 2026 से जारी वाद–विवाद प्रारंभ होगा ।

माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना पक्ष रखें, आपका समय 25 मिनट का है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद के लिए हमको मौका देने के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं और हमलोग उस दिन उनका अभिभाषण सुनें, देखें और पढ़ें और लगभग 2015 में हम पहली बार सदस्य चुनकर आये थे, अब लगभग यह 11वां साल चल रहा है और 11 साल में कई राज्यपाल आयें और कई राज्यपाल गयें महोदय । लेकिन जो भी माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का वक्तव्य 11 सालों से वही पुरानी बातें, वही पुराने शब्द, वही हू–ब–हू जो 11 साल से सुनते आये हैं वही भाषण में, दो–चार चीजों को छोड़ दिया जाए तो सारा वही चीज है और जो अधिकारी जो सरकार बनाकर के देता है वह राज्यपाल पढ़ते हैं और वही महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा है लेकिन सच्चाई क्या है, धरती पर बिहार की स्थिति जो है ग्राउंड पर, वह क्या है वह बिहार की जनता और देश की जनता और सत्तापक्ष के लोग भी जानते हैं लेकिन सत्ता में जो लोग हैं । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार की दो पहचान है, एक झूठी वाहवाही और हन्ड्रेड परसेंट लापरवाही, यही जो सच्चाई है महोदय यह हमलोगों ने देखा है । पिछला चुनाव संपन्न हुआ महोदय, नई सरकार बनी और पूरा देश जानता है कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीती महोदय और अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र को इनलोगों ने धनतंत्र और मशीनतंत्र बना दिया । हालांकि, अब जैसे–तैसे लोग सरकार में आये हैं लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि सरकार आयी है लगातार 20 साल से भी ऊपर आपलोगों की सरकार है और बिहार के विकास में कभी भी सहयोग अगर आपलोगों को चाहिए तो विपक्ष जो है हमेशा मजबूती के साथ खड़ा है, भले ही संख्या हमलोगों की कम है लेकिन हमलोग निडर होकर के बिहार की जनता की आवाज को सदन में उठाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाते रहेंगे । अध्यक्ष महोदय, हम राज्यपाल महोदय जी के भाषण को हमलोगों ने सुना, कानून का राज है, ऐसी बातें की गयीं, न्याय के साथ विकास है, न्याय तो नहीं लेकिन अन्याय के साथ विनाश ही हो रहा है पूरे बिहार में । महोदय, कानून के राज पर तो हम अभी जायेंगे कि क्या कानून का राज है, उस पर भी हम जाना चाहेंगे लेकिन आप देखिएगा यह पूरा भाषण हमारे पास पड़ा हुआ है। जो हमलोगों का विजन, जो हमलोगों की महागठबंधन

की सरकार दो बार आई 2015 से 2017 या 2022 से हमलोग लगभग 18 महीने, 17 महीने सरकार में रहें वो, आप कोई भी पन्ना खोलिए, पहला पेज के बाद से दूसरा पन्ना जाइये तो शिक्षक की बहाली, उसमें तारीख भी है बी0पी0एस0सी0 का 2023 में, किसकी सरकार थी महोदय, महागठबंधन की सरकार थी और 10 लाख नौकरी देने का वादा किसका था और किसकी सरकार में हुआ यह बिहार की जनता जानती है....

(व्यवधान)

चाहे नियोजित शिक्षकों को मौका देने की बात हो, तालिमी मरकज हों, विकास मित्र हों, टोला सेवक हों, उनके मानदेय को बढ़ाने की बात हो तो ये सारा काम जो है महोदय, हमारी सरकार में हुआ । वही नीतीश कुमार जी जो 2020 में जब हम कहते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहां से लायेगा, अपने बाप के पास से पैसा लायेगा। महोदय, यह वीडियो सब लोगों ने देखा है और यही नहीं हमलोगों ने चुनाव में कहा कि मुफ्त में 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, पेंशन बढ़ायेंगे, महिलाओं के लिए माई–बहन मान योजना लायेंगे, सारा चीज जो है महोदय वही कॉपी की गयी है, यह किसी से छुपा नहीं है महोदय । यह आप देख लीजिए, सारा आप देखियेगा जितनी योजनाएं सात निश्चय–1 की जो योजना है महोदय वहीं से शुरुआत उसकी की गयी है तो सारा काम तो जो हमलोगों ने कहा वही बात राज्यपाल जी ने वही कहा है महोदय । महोदय, और यही नहीं हम कहना चाहते हैं उस दिन मुख्यमंत्री जी हमको कह रहे थे सदन में, सेंट्रल हॉल में कि ताली जो है वह पीटो । हम तो मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे कि हमारे ही काम, हमारी ही विजन को लेकर के सत्तापक्ष के लोग ताली बजा रहे थे, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है । महोदय, अब बात है कि भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति जो सदा से ऐसी भाजपाइयों कि बिहार में महिलाओं से सदा.....

(व्यवधान)

सुन लीजिए, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, 10–10 हजार रुपया आपलोग दिये चुनाव में और आपके उत्तराखंड में भाजपा के नेता क्या कहते हैं कि 20–25 हजार में महिलाओं को खरीदा जाता है, महिलाएं बिकती हैं महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : सुन लीजिए ।

अध्यक्ष : शांति बनाए रखें, प्लीज बैठ जाएं । कृपया शांति बनाये रखें, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का, बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

बिना अनुमति के कृपया मत बोलें, आप सबों से अपील है कि बिना अनुमति के मत बोलिए, आपको मौका मिलेगा बोलने का आप उसमें अपनी बातों को रखिएगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, विडंबना यह हो गयी है कि सरकार की नींद, सरकार की नींद.....

(व्यवधान)

चिंता मत कीजिए, आपलोगों ने तो लोकतंत्र को डरतंत्र बना दिया है महोदय, जो सच्चाई है । महोदय, सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं और हम कहना चाहेंगे अपराध इतना बढ़ गया है हम मामूली बातें.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाये रखें ।

श्री भाई बीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के पैर में दर्द है, वह टिस मार रहा है इस वजह से ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : इन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज है क्या ?

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष । बिना अनुमति के कृपया खड़े न हों, आपलोग बैठ जाइये, सबको मौका मिलेगा उसमें अपनी बातों को रखिएगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति है तो क्योंकि मेरा पूरा नाखून ही कवर चुका है, दर्द बहुत ज्यादा है, एंटीबायोटिक में हम चल रहे हैं तो अगर आपकी अनुमति है तो हम बैठकर अपनी बातों को रखेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । आप बैठकर बोलिए ।

टर्न–11 / सुरज / 05.02.2026

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, कुछ घटनाएं हम बताना चाहेंगे कि इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है और बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि यह सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है । हमने पहले भी कहा कि इनलोगों ने डरतंत्र बना दिया है और बिहार में अपराधियों में डर नहीं बल्कि सरकार में शर्म भी नहीं है । अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म नहीं ।

महोदय, मैं कुछ विगत घटनाएं पूरे जिले के बारे में मैं रखना चाहता हूं । पटना के नीट छात्रा की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिला के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और तीन बच्चों की अपहरण बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमुर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, मुंगेर में महिला की हत्या, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या, कटिहार में महिला की संदिग्ध हत्या, सोनपुर में महिला की हत्या, मुजफ्फरपुर में 5 वर्षीय मासूम से रेप, गोपालगंज के भोरे में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, मोतिहारी के पताही में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक, गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, छपरा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, दरभंगा में

पी0एच0ई0डी0 कर्मी की हत्या, पूर्णिया में युवा व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या, बेगुसराय में युवक की हत्या, बेगुसराय में मासूम लड़के की हत्या, मुजफ्फरपुर में दरोगा को सरेआम पीटा गया, नालंदा में ट्रांसपोर्टर की हत्या, भोजपुर में नाबालिग की अपहरण बाद हत्या, बेगुसराय में दुकानदार की अपहरण बाद हत्या, औरंगाबाद में युवक की हत्या, पश्चिम चंपारण में युवक की हत्या, वैशाली में युवक की हत्या, सीतामढ़ी में अधेड़ की हत्या, सहरसा में युवक की अगवा कर हत्या, पूर्वी चंपारण में युवक–युवती की हत्या ।

महोदय, हम जानना चाहते हैं एक तो अभी लाल शुटकेश में पूरा डेडबॉडी मिला है, आपलोग देखे होंगे । कहां है कानून का राज, क्या हो रहा है बिहार में ? लेकिन इन लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा । क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि जंगल राज नहीं कहना, नहीं तो जंगल राज को मानने वाले जानवर यह सुनकर नाराज हो जायेंगे । महोदय, यह स्थिति है । आप देखियेगा, सत्ता पक्ष के साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि :

आईना जब भी उठाया करो,
पहले खुद देखा करो,
फिर दिखाया करो ।

महोदय, सच्चाई है कि थाना खमोश है, प्रशासन बेहोश है और सरकार पूरी तरह मदहोश है । जनता में इस सरकार के लिए अफसोस और आक्रोश है । बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज बन चुकी है । हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई रहती है । यह बिहार सरकार की सच्चाई है ।

महोदय, अब बात अगर किया जाए तो हम लगातार एक बात सभी लोग यहां सत्ता में बैठे हैं उन सबसे हम पूछना चाहते हैं कि बिहार जब इतना विकास कर रहा है, बिहार जब इतना आगे बढ़ रहा है तो हमको एक बात बताइये कि बिहार आखिर किस चीज में नंबर वन है और राज्यों के मुकाबले ? बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा के मामले में फिसड्डी है, स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी है । सब लोग तबाह हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में अव्वल है । आप देखियेगा अपराधियों को बोलबाला है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम है । किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लोग तफरा–तफरी किये हुए है । जिन गरीबों का आपलोग दावा करते हैं कि वोट लिया, उन गरीबों के घर को उजाड़ने में आप लगे हुए हैं । यह बिहार की सच्चाई है । बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय है, औसत अगर दिखाया जाए तो लगभग हजार से 11 सौ डॉलर है । बिहार अगर अलग देश होता तो पूरे दुनिया में सबसे गरीब देश होता । जो सब सहारा अफ्रीका के जो देश हैं जो माना जाता है विश्व में सबसे गरीब देश । आज बिहार उससे भी गरीब राज्य होता । महोदय, यह सच्चाई है ।

अध्यक्ष महोदय,

मंजूर नहीं था भाजपाइयों की शर्तों पर सुल्तान बनना,
क्योंकि हम अपना जमीन और विचार नहीं बेचते,

भले ही फकीर बन जाएं ।

अभी कुछ भी बोलिये, कहिये, कराइये अभी आपका समय है । हमारा दौर आयेगा ।

सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास,
कुछ तलाब खुद को समुन्द्र समझ बैठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, 1960 में जहां बिहार खड़ा था, आज 2026 में भी बिहार वहीं खड़ा है । चाहे गरीबी दर देख लीजिये, प्रति व्यक्ति आय देख लीजिये । इन सब में बिहार अभी आगे बढ़ा नहीं है । आपलोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है लेकिन सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है पूरे देश में । क्या चीज में नंबर वन है जरा यह तो बताइये । हमलोग यह कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि बिहार के विकास के लिये हमलोग, सबलोग खड़े हैं । जहां विपक्ष की जरूरत पड़े हमलोग एकदम साथ देंगे । हम तो कहना चाहते हैं जितने हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि बिहार आगे तब बढ़ेगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलेगा और हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि एकदम विशेष राज्य के दर्जे की मांग को हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि डबल इंजन की सरकार है । सुनियेगा महोदय, डबल इंजन की सरकार है, डबल उप मुख्यमंत्री हैं, डबल सेन्चुरी में विधायक हैं, डबल डिजिट में आपके सांसद हैं । अब नहीं आगे बढ़ाइयेगा तो कब बढ़ाइयेगा और डबल डिजिट में आप बिहार में 20 साल से राज कर रहे हैं फिर भी बिहार 1961 में जहां खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है । हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी को चलिये आंदोलन करते हैं, चलिये मजबूती के साथ आप प्रधानमंत्री जी के साथ, पूरा प्रतिनिधिमंडल, बिहार का सदस्य, सभी पार्टी के लोग चलते हैं और विशेष राज्य की मांग और विशेष पैकेज की मांग आप कीजिये, हमलोग सपोर्ट करने का काम करेंगे । क्योंकि यह बात कई बार मुख्यमंत्री जी तो बात भूल जाते हैं, अब मुख्यमंत्री जी तो भूल गये । बिजेन्द्र जी हैं यहां जब हम 200 यूनिट की बात किये तो मुख्यमंत्री जी, इसी सदन में उनका भाषण है न कि मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिये । आखिर क्या मजबूरी आ गयी कि सवा सौ यूनिट बिजली भी मुख्यमंत्री जी को देना पड़ रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न–12 / धिरेन्द्र / 05.02.2026

....क्रमशः....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हाँ, बिहार नंबर वन इसमें भी है कि सबसे ज्यादा महंगी बिजली अगर कहीं मिलती है पूरे देश में तो वह बिहार है, सबसे महंगी बिजली । महोदय, मेरे पिता कहते हैं कि बाज बनो, ऊँची उड़ान लगाओ और जिंदगी में बाज बनिये, जब तुम बाज बन जाओगे तो तोता, मैना, कौआ नीचे–नीचे उड़ेंगे । अगर कोई और मुकाबला करे तो बाज बन कर और ऊंचा उड़ो ताकि कौआ, तोता, मैना इतनी ऊंचाई पर उसको ऑक्सिजन नहीं मिलेगा, वह नीचे गिर जायेगा । महोदय, इस पर इतना ही कहना चाहूँगा–

रोक सकी है आंधियां कब इसकी परवाज,
उड़ता है बेखौफ वो आसमां में बाज ।

हम तो यह कहना चाहेंगे कि हमलोगों ने जब महागठबंधन की सरकार थी 65 फीसदी आरक्षण लाया, ई॰डब्ल्यू॰एस॰ का 10 फीसदी कुल मिलाकर 75 फीसदी आरक्षण हमलोगों ने रखा था । आखिर उस आरक्षण का क्या हुआ ? नौवीं अनुसूची में हमलोगों ने बोला था कि इसको आप डलवाने का काम कीजिये लेकिन अभी भी मामला ठंडा है, कोर्ट में फंसा है या कानून ही खत्म कर दिया गया है । हम तो फिर से चाहेंगे कि आपलोग एक नया बिल लाइये, 65 फीसदी नहीं बल्कि 85 फीसदी कर दीजिये, समर्थन हमलोग देते हैं, पास कराइये और केन्द्र को प्रस्ताव भेजिये, कैबिनेट से भी भेजिये और विधान सभा से भी प्रस्ताव भेजिये कि जो आरक्षण है उसको नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाय लेकिन कहीं कोई इस पर चर्चा नहीं होती है, कहीं कोई बात इस पर नहीं होती है कि इसे किया जाय लेकिन अब उम्मीद ही क्या किया जाय । भाजपा आरक्षण विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है, भाजपा लोकतंत्र का विरोधी है, संविधान का विरोधी है, यही भाजपा का असली चरित्र है जो ट्रंप कहेंगे वही होता है । हमको तो लगा कि नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन अब तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ही देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं । इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा, इतनी बार डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात हो वही घोषणा, सीजफायर की बात हो वही घोषणा करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा अब तक डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी है । महोदय, पूरी तरीके से ये सरकार जो है डबल इंजन और आप देखियेगा कि चुनाव जब आता है तो बहुत लोग घोषणा किये, उसमें सम्राट चौधरी जी भी आगे–आगे खड़े थे भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री । महोदय, इनका तो ये हाल है कि जब बिहार में चुनाव होने थे तब घोषणा की गयी कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलेगी । महोदय, अब बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है, अब बंगाल में चुनाव है तो पहला वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन अब कोलकत्त से गुवाहाटी चलेगी, यही तो स्थिति है इन लोगों की । जहाँ–जहाँ चुनाव है, बिहार का पिछला चुनाव था तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जो थीं निर्मला जी, मधुबनी साड़ी पहन कर आयी थीं अब....

(व्यवधान)

और महोदय, अब तमिलनाडु में चुनाव है तो वहां के रंग की साड़ी पहन कर भाषण दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, यह केवल दिखावा है । चुनाव में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : गायत्री जी, कृपया बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, चुनाव में कई केन्द्र मंत्री आयें, भाजपा के कई राज्य के मुख्यमंत्री आयें, आर॰एस॰एस॰ का संगठन आया,

प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आते रहें, अब बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो ये लोग बिहार भूल गये हैं । अब बिहार से कोई मतलब नहीं । चुनाव हराने के लिए...

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, आपके पास अब एक मिनट का समय है । कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, दो मिनट । महोदय, हम इतना कहना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए धनतंत्र, क्या ताकत इन लोगों ने नहीं लगाई, मशीनतंत्र लगाया गया, बिहार सरकार, भारत सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, पूंजीपति, चालिस हजार करोड़ से भी ज्यादा रुपये बांटे गये केवल हमलोगों को चुनाव हराने के लिए लेकिन इससे हमलोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इतना कहना चाहते हैं कि–

मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारों,
जो चट्टानों से न उलझे वह झरना किस काम का ।

तंत्र से बनी यह सरकार बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और पलायन पर नियंत्रण करे । प्रदेशवासियों को जो वादे किये थे वह वादा पूरा किया जाय । अब देखते हैं कि आप लोग कितने जिलों में कारखाना लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं। एक करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया गया है, रोजगार देने की बात कही गयी है । बताइये कि कौन–सी नौकरी दीजियेगा, कौन–से रोजगार में व्यवस्था कराइयेगा या जो आज पकौड़ा तल रहा है वह भी आप ही लोगों की देन है क्या, रोजगार जो दे रहे हैं तो उसे कैटगराइज तो कीजिये ।

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, कृपया समाप्त करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट । एक मिनट में हम समाप्त कर रहे हैं । हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते है, हम लास्ट में केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमलोग भी देख रहे हैं और बिहार की जनता भी देख रही है कि अब बिहार सरकार जो है बिहार के लोगों के लिए क्या कर रही है और हम सरकार से आग्रह बार–बार करते हैं कि करनी और कथनी में अंतर मत रखिये । आप ईमानदारी से बिहार की सेवा कीजिये और अगर आपलोग सेवा कीजियेगा, काम कीजियेगा तो हमलोगों का साथ पाइयेगा, गलत काम कीजियेगा तो उसमें हमलोग आवाज उठाते रहेंगे तो इसलिए आप सब लोगों से यही निवेदन है, चाहे सत्ता पक्ष के भी लोग हैं नये लोग जो चुनाव जीत कर आये हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आपलोग जनप्रतिनिधि हैं, आपलोगों की बात कितनी सुनी जाती है ? कोई अधिकारी सुनता है ? फोन उठाता है ? काम होता है ? महोदय, कुछ नहीं होता है ।

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, कृपया समाप्त करें । आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ । आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय बाबू, कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की पीड़ा को हमलोग समझते हैं और हमलोगों ने आपसे आग्रह भी किया कि उनको बैठकर बोलने का इत्मीनान से अवसर मिले । अध्यक्ष महोदय, यह सदन कई इतिहास का गवाह और

आजादी से पूर्व और आजादी के बाद हर उस क्षण का गवाह रहा, उस गवाह के हम भागीदार नहीं बन सकें लेकिन आज भी प्रोसीडिंग में वह पार्ट मौजूद है कि इस सदन में क्या–क्या सकारात्मक और नकारात्मक खेल हुआ । महोदय, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि गलत करने का, तो गलत करने का सारा ठेका इनके जिम्मे था, सारी ठेकेदारी तो ये लिये थे । आज मैं बता दूं कि जंगलराज के युवराज, पूरा बिहार नहीं देश जानता है कि जंगलराज का युवराज कौन, जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले के गोद में बैठकर और जंगलराज के युवराज लोकतंत्र को परिवारतंत्र में बदलने वाले संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले और जानवरों का चारा तक चुरा लेने वाले ऐसे मानसिकता के लोग उपदेश कतई नहीं दें । महोदय, नई सरकार की नई पहल है सुशासन से समृद्धि और डबल इंजन की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री विकसित बिहार बनाने के सपने को साकार करने का जो संकल्प लिया है उसकी एक मजबूत नींव रखी गयी है । महोदय, इन्होंने जिन अपराधियों के डर की बात कहते हैं...

...क्रमशः....

टर्न–13 / अंजली / 05.02.2026

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, गवाह है बिहार कि नरसंहारों में माँ–बहनों की चूड़ियां और सिसकियां फूटती थीं, वह नरसंहार एन0डी0ए0 सरकार ने खत्म की । महोदय, एक बार में विधवाओं की झुंड चूड़ियां नहीं फोड़ती । महोदय, बी0डी0ओ0 आप थे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें । बैठे–बैठे मत बोलिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : बी0डी0ओ0 आप थे, आपका इतिहास मैं जानता हूं, श्रवण बाबू भी आपका इतिहास रखे हैं, घबराइए मत । हम आपके इतिहास और भूगोल को भी जानते हैं ।

अध्यक्ष : प्लीज, बिना अनुमति के मत बोलिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, ये महिलाओं के प्रति चिंतित हैं, जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति और परिवेश का सम्मान नहीं करें, जो अपने घर की बहू–बेटी का सम्मान नहीं करें, वह बिहार और देश की महिलाओं की बात करें, यह कैसे संभव है ? महोदय, आज प्रधानमंत्री जिसको पूरा देश ही नहीं, दुनिया नेता मानता है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं कि वे हमारे नेता हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना अनुमति के मत बोलिए । विजय बाबू, बोलिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : आप देखिए, छटपटाहट में है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए । भाई वीरेन्द्र जी, बैठ जाइए । बिना अनुमति के मत बोलिए । प्लीज।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : ये लोग जंगल राज वाले, जंगल राज वाले मानसिकता के लोगों की बेचैनी, घबराहट में बदल रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इन बातों को प्रोसीडिंग में नहीं ली जायेंगी । बैठिए, प्लीज । बिना अनुमति के मत खड़ा होइए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, बिहार के इतिहास में जब जंगल राज का, नरसंहार का, सामाजिक उन्माद का, पूरा बिहार थरथरा रहा था, पलायन कर रहे थे अच्छे लोग, श्रद्धेय अटल बिहारी वायपेयी जी ने बिहार के अपने भारत के कैबिनेट मिनिस्टर के लोग ही कैबिनेट मिनिस्टर को बिहार भेजे थे सुशासन के लिए और जिस व्यक्ति ने आज बिहार के चेहरा और विकास को बदला उनपर कॉमेंट ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें । सौरभ जी, बिना अनुमति के मत खड़ा होइए । बैठिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : ऐसी मानसिकता के लोग, ये पूरी तरह से अराजकता के शिकार हैं, बिहार की जनता लोकतंत्र में आपको नकार दिया, आपके नकारात्मक बातों से आपको मुक्त कर दिया, आपको चिंतन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि जनता ने आपके भौकाल को खत्म कर दिया, अब भौकाल से नहीं चलेगी व्यवस्था, जनता के सरोकार से चलेगी व्यवस्था । आज जनता ने 20 वर्षों के बाद इतिहास रचाया कि जो 20 साल शासन में रहें और इतना बड़ा जनादेश जनता ने बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिया है उसके बाद भी ये कहते हैं शर्म नहीं, शर्मसार तो आपको होना चाहिए कि आपके भौकाल को जनता ने नकार दिया । जो जनता के सरोकार से काम कर रहा है उस पर विश्वास व्यक्त किया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठे–बैठे मत बोलिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : ये माहौल खत्म करिए । महोदय, मैं यही आग्रह करूंगा कि चिंतन करने की जरूरत है, चिता मत बनाइए, आने वाले दिनों में लोकतंत्र की चिता बनाने की मानसिकता को चिता में बदल देती है बिहार की जनता यह याद रखिए । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना अनुमति के मत बोलिए । प्लीज, बिना परमिशन के बैठ–बैठे मत बोलिए । बिना अनुमति के कही गई बातें प्रोसीडिंग में नहीं ली जायेंगी । माननीय सदस्य, श्री सुनील कुमार पिन्टू । अपना पक्ष रखें ।

(व्यवधान)

प्लीज, बैठकर मत बोलिए । कृपया शांति बनाए रखें । बिना अनुमति के कृपया मत बोलिए, अनुमति लेकर बोला जाता है । मौका मिला है न बोलने का । आपके पास 8 मिनट का समय है । बोलिए ।

श्री सुनील कुमार पिन्टू : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, जब बिहार में 2005 में एन0डी0ए0 की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पक्ष में बिहार की जनता ने मतदान देकर जब बैठाया तो उनका सबसे पहला संकल्प था और जो जनता को उन्होंने वायदा किया था कि न्याय के साथ विकास और 2005 के बाद इस राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार प्रयास किया, जिसके कारण आज बिहार के अंदर में कानून का राज स्थापित है । आज 112 डायल, अगर कहीं भी कोई एक छोटी–सी घटना–दुघर्टना हो जाय, आप पुलिस को बुला सकते हैं, पुलिस पहुंच रही है, त्वरित कार्रवाई हो रही है जो कि कल दिन तक थाने तक फोन करना या थाने में बात हो जाना एक दुर्लभ चीज कही जाती थी, आज यह है कानून का राज ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिये । आपस में बात न करें । सबको मौका मिला है, इनकी बातों को सुनिये ।

श्री सुनील कुमार पिन्टू : अध्यक्ष महोदय, कानून का राज स्थापित है यह विपक्ष के सुप्रीमो आदरणीय लालू जी भी कहते हैं, खुद शाम में मरीन ड्राइव पर टहलने जाते हैं कि बिहार में कानून का राज स्थापित है, वे खुद इस बात की गवाही देते हैं कि बिहार में कानून का राज है । विपक्ष के लोगों को उनसे यह बात को समझनी चाहिए थी । नेता विपक्ष ने कहा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें । मेरा आग्रह है आपस में बात न करें । बिना अनुमति के मत बोलिए । संजय जी, बैठ जाइए । व्यवधान पैदा मत कीजिए ।

श्री सुनील कुमार पिन्टू : महोदय, नेता विपक्ष ने कहा कि हम 11 साल से इस सदन में हैं, महोदय, मैं 2003 में पहली बार इस सदन में आया था । उस समय हमलोगों के नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी थे और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उस समय में नेता विरोधी दल थे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया टोका–टोकी न करें । शांति से बातों को सुननी चाहिए । आप बोलिए ।

श्री सुनील कुमार पिन्टू : अध्यक्ष महोदय, 2003 में मैं जब पहली बार सदन में आया था, आज 23 साल हो गया है, नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि 11 साल उनका हुआ है, उनसे दोगुना का तजुर्बा मैं बतला रहा हूं कि उस दरम्यान में आदरणीय सुशील मोदी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार में जो हर एक जगह घटनाएं दो दिन पर होती थीं, ये दोनों आदमी सुबह–सुबह निकलते थे उस जिले में, जहां कोई घटना होती थी । आज बिहार में अमन–चैन–शांति है । हमारे नेता प्रतिपक्ष हर हफ्ते विदेश घूमने जा रहे हैं कि बिहार में कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां जाकर मिजाजपुर्सी कर सकें । उसके कारण...

(व्यवधान)

माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बाज बनो, सही में आप बाज बन गए हैं कि अपना जन्मदिन तक हवाई जहाज में आकाश में मनाते हैं और आए दिन हवाई जहाज से विदेश घूमते हैं, सही अपने पिता की बात मानते हुए बाज बनने का काम किया है, ये बाज आप जरूर बने हैं । महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री सुनील कुमार पिन्टू : महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो बिहार में लगातार आर्थिक पैकेज मिला है जिससे बिहार में चारों ओर लगातार जो विकास...

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : इन सब का सुनिए । आप लोग आज तक कोई काम किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं । चुप–चाप इनकी बातों को सुनिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं । बैठ जायं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पर सवाल उठाए हैं । महोदय, हम इतना कहना चाह रहे हैं कि...

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार पिन्टू : मेरा विपक्ष के सभी भाइयों से आग्रह होगा कि जब कभी आप पटना एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपने देखा होगा पटना एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट है । विकास कहां है, यहां है । विकास आपको सामने में दिख रहा है ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय...

अध्यक्ष : बैठिये । प्लीज । तेजस्वी जी, बैठ जाइए । प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार पिन्टू : हमलोगों ने आपकी बात सुना, आप भी हमारी बात सुनिये । महोदय, 7 निश्चय में नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कहां नौकरी बंटी है ? दस लाख नौजवानों को नौकरी मिली है और दस लाख लोगों को रोजगार दिया गया है यह हुआ है । उसके अलावा अभी सात निश्चय में 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है आलरेडी । महोदय, अब अगला टारगेट रखा गया है कि इसे और बढ़ाकर एक करोड़ तक लोगों को रोजगार और नौकरी देने का 7 निश्चय के अंतर्गत करने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप संक्षिप्त करें ।

टर्न–14 / पुलकित / 05.02.2026

(क्रमशः)

श्री सुनील कुमार पिंटू : महोदय, इन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री ट्रम्प के सामने झुक गये । ट्रम्प नहीं, पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री के सामने झुकी है । प्रधानमंत्री ने अपनी शर्त पर ही समझौता पर दस्तखत किये । आज आप देख रहे हैं कि क्या रूस, क्या चाईना, क्या अमेरिका, तीनों इंडिया के प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं कि कल इनका फैसला क्या होगा । उस पर दुनिया चलनी है, उस पर पूरा देश चलना है ।

आज हमारे बिहार के अंदर में, बिहार ही एक ऐसा राज्य है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं ।

श्री सुनील कुमार पिंटू : बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां सभी धर्मों का समावेश है ।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सुनील कुमार पिंटू : अध्यक्ष महोदय, हमारे बोलने के समय ज्यादा शोरगुल हो रहा था । हमें दो मिनट का समय और दिया जाए । अध्यक्ष महोदय, बिहार ही एक ऐसा राज्य है, जहां सभी धर्मों का समावेश है । बिहार में ही सीतामढ़ी में मां जगत जननी सीता की प्रकट स्थली है । पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है जो सिख धर्म के है । भगवान महावीर का भी जन्म यही हुआ है । उसके अलावा बुद्ध को, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई । इस प्रकार और वर्ल्ड की पहली महिला सूफी जहानाबाद काको से हुई थी । बिहार के अंदर में टूरिज्म की जो जितनी बड़ी, सबसे ज्यादा यहां लोगों को आने की उत्सुकता है।

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री सुनील कुमार पिंटू : आज बिहार में अमन और शांति के कारण आप देखेंगे कि बिहार में लगातार लोगों का आना हो रहा है, टूरिज्मों की संख्या में लाखों से करोड़ों तक की आज आप देखेंगे तो बिहार के अंदर में लोग आ रहे हैं । इसलिए मेरा आपसे अध्यक्ष महोदय अनुरोध होगा कि....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं ।

श्री सुनील कुमार पिंटू : ठीक है, अध्यक्ष महोदय । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद–विवाद पर अब सरकार का उत्तर होगा । अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

कोई भी सदस्य बैठे–बैठे नहीं बोलेंगे । कोई भी सदस्य बीच में नहीं बोलेंगे । अनुशासन बनाए रखिये । कृपया शांति बनाये रखें ।

(व्यवधान)

बिल्कुल । आसन की बिना अनुमति के कोई सदस्य नहीं बोलेंगे ।

सरकार का उत्तर

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम बिहार विधान सभा के बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ । बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है । मैं बिहार विधान सभा के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं को विस्तार से बताया है । इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । आप सब जानते हैं कि 24 नवम्बर 2005 को पहली बार एन0डी0ए0 की सरकार बनी थी । तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं । याद है न पहले क्या स्थिति थी ? पहले बहुत बुरा हाल था । लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे ।

(व्यवधान)

सुनिए न पहले । हमलोगों के पहले जो आपलोगों का राज था, क्या था? कोई काम था ?

अध्यक्ष : कृपया बीच में मत बोलिये । बिना अनुमति के बीच में मत बोलिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे । शाम के बाद कोई बाहर जाता था ? शाम के समय लोग घर में ही बैठे रहते थे ।

(व्यवधान)

यही न आपलोगों का हिसाब था ? और समाज में कितना विवाद होता था ? कितना हिन्दू–मुस्लिम झगड़ा होता था ?

पढ़ाई का क्या हाल था ? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे । बहुत कम पढ़ाई होती थी । पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था । सड़कें बहुत कम थी और जो सड़कें थी उनका बुरा हाल था और बिजली बहुत कम जगह थी। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है । अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है । राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है।

पहले कितना हिन्दू–मुस्लिम झगड़ा होता था ? इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई । बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है । अब कोई झगड़ा–झंझट नहीं होता है । उसके बाद भी वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिन्दू मंदिरों की घेराबंदी की गई जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है ।

(व्यवधान)

यह सब जो गड़बड़ थी, वह सब हमलोगों की सरकार में शुरू में ही खत्म की गयी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हर बात पर बोलने की जरूरत नहीं है । कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : वर्ष 2006 में ही जब इनलोगों की तरफ से कुछ काम था नहीं, तब 2006 से काम शुरू किया गया और बाद में फिर हमलोगों ने देखा कि उसको

भी इधर–उधर जाकर के कुछ थोड़ा बहुत शाम में करता था, तो हमलोगों ने 2016 में भी यह सब काम किया ।

अब उसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हमलोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की । लड़के–लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई । वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई । वर्ष 2006 में उन लोगों को कर दिया था, पूछ रहे थे कि आप ही लोग कर लीजिए, तो 2006 से 3 लाख 68 हजार नियोजित शिक्षक बने थे । जब बाद में 2023 में इतना कर रहे थे, इसमें से भी कुछ लोग शामिल हुआ था । उसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 हजार और 976 सरकारी शिक्षक बन गए । फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बी0पी0एस0सी0 की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है । उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए । इसके लिए उन्हें पांच मौके तय किए। अब तक चार परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है।

अब बाद में तो हमलोगों ने कर दिया कि जो बाकी था, शुरू में कर दिए थे हम लोग इसमें, जो कुछ भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किए थे, तो उसके चलते फिर बाद में कोई कह दिया कि यह नहीं करेगा, उसके लिए अन्य प्रकार से हमलोगों ने करवा दिया । उसके लिए फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को बी0पी0एस0सी0 की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है । उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए । इसके लिए उन्हें पांच मौके तय किए । पांच मौका हमलोगों ने तय किया और उसमें से चार परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है । जिसमें 2 लाख 66 हजार नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं । अब केवल 73 हजार शेष बच गए हैं, तो उन्हें एक मौका और दिया जा रहा है और उसके लिए ये सब काम जितना भी संभव होगा, वह करेंगे ।

अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 24 हजार हो गई है । स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया । पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही आते थे । यानी प्रतिदिन एक या दो मरीज आते थे । वर्ष 2006 से अस्पतालों में यह पहले वाली बात है जब हमलोगों की सरकार बनी थी उसके पहले वाली जो स्थिति थी उसके बारे में हम कह रहे हैं कि पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही होते थे, वहां प्रतिदिन एक या दो मरीज ही आता था । यह सब देखकर बहुत खराब लगता था । वही हमलोगों के द्वारा 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी गई । अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर महीने औसतन 11 हजार 6 सौ मरीज आते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–15 / हेमन्त / 05.02.2026

(क्रमशः)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : पहले मात्र छः मेडिकल कॉलेज थे और इन लोगों की सरकार जो बनी थी, समझ गये, 7 दिन में तो पिताजी चले गये और अंत में फिर माताजी को रख दिये। तो इसी तरह से किसी को कुछ बनाये थोड़े ही थे, लड़की, लड़का किसी को कुछ नहीं, तो वही होता था वहां। तो इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं हुआ, तो उसके चलते सब तरह से यहां पर आप समझ लीजिए कि शिक्षा के बारे में तो हम बता ही रहे हैं आपको। फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उनसे मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। इसके लिए उन्हें चार–पांच मौके तय किये, अब तक चार परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें दो लाख छियासठ हजार नियोजित शिक्षक पास हुए हैं और उसके बाद अब केवल 73 हजार शेष बच गये हैं, हम पहले ही बता दिये हैं कि इतना कम बच गये हैं। अब कुल–मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 24 हजार हो गयी है। स्वास्थ्य के बारे में जो बात हो रही है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना था, 39 था और एक दिन में एक या दो मरीज होते थे, वह बहुत खराब था। तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गयी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11 हजार 600 मरीज आते हैं। पहले कितना खराब था उन लोगों का। अब उसके चलते तुरंत बाद हम लोगों ने 2006 में किया, तो उसके लिए 11 हजार 600 मरीज सब जगह इलाज के लिए जाते रहे। पहले क्या स्थिति थी, यह तो हम पहले बोले ही थे, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, थोड़ा तो हम बढ़ाये हैं, 12 तो हो गया, बाकी उसके अलावा 27 हम कर रहे हैं। 27 जिलों में नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं जिनको बहुत शीघ्र पूरा किया जायेगा। यह बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत जल्दी यह भी हो जायेगा। अब मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5 हजार, यह तो पहले वाले जो थे 6 ही थे, उनके लिए तो हम लोगों ने ज्यादा बढ़िया किया और बराबर हम जाते हैं। कल भी हम नहीं गये ? जो थोड़ा–सा है, हमने कहा कि जल्दी करिये, इतने अधिकारियों को हम ले जाते हैं और हम लोगों ने तय कर दिया है, बहुत ज्यादा बना है। आप समझ लीजिए, पटना मेडिकल अस्पताल को हम बना देंगे पूरा, अभी और बन रहा है, थोड़ा बना है, बढ़ा है, लेकिन और सब बन रहा है, उसको हम जा–जाकर देखते हैं कि जल्दी इतना आगे और बनाइये 5400 बेड तथा बाकी जितने हैं 5 मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड का किया जा रहा है, वह भी हो रहा है। सबके लिए हम करवा रहे हैं कि तेजी से करिये और वह हो जायेगा। उसके बाद तो आप जानिये आईजीआईएमएस पटना में था, उसके लिए भी हम सब जगह जाकर, देखकर कितना ज्यादा हम बढ़वाये। बहुत बढ़वाये हैं और वह चल रहा है। उसके लिए भी हम लोगों ने कह दिया, तो 3000 बेड का बनाया जा रहा है, कुछ तो बनाया ही गया है और भी बन जायेगा, सब कुछ हो रहा है।

राज्य में सड़कों का, पुल–पुलियों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर, अब उसके लिए हम लोगों ने 2008 से....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपस में टोका–टोकी नहीं करें।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है और वर्ष 2008 से 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा और फिर चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। इसलिए कुछ–कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं कि कितना काम हो रहा है सरकार की तरफ से। वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया।

(व्यवधान)

अरे भई, इन लोगों को ले लिये थे, तो हम ही जो तैयार किये हुए थे, ये लोग आये थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, इसी को फिर बना दिये थे और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर–उधर नहीं करता था और उसके बाद अब इधर से उधर करता....

(व्यवधान)

बैठो, बैठो न तुम। अरे, कुछ नहीं बैठो। क्या करते थे ? इधर से उधर करते थे। इस बार जो तुमको रखे थे, तो तुम कितना इधर से उधर करके, लोगों को खींचने के लिए छः आदमियों को कितना पैसा तुम दिये थे ? पैसा कहां से लाये थे, तुमको मिल गया था, तो पैसा कमाते थे। तो इसी के चक्कर में थे। इसीलिए हम छोड़ दिये सब।

(व्यवधान)

तो अब देख लीजिए सर। सर, देखिये। अरे, बैठो न। सर, 2025 के बारे में हमने बता दिया कि हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। वर्ष 2018 में ही, पहले तो कुछ नहीं था सर, पटना में आठ घंटा थोड़ा–बहुत रहता था, नहीं था। हम लोगों ने शुरू से किया कि सबको होना चाहिए, तो 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गयी। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गयी। शुरू में तो हम लोगों को बहुत पैसा लगा था फिर बाद में हमने तय कर दिया कि नहीं, इसको मुफ्त में देना है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, मुफ्त में अब सबको दिया जा रहा है। अब सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाये जायेंगे। हम सबको कहते हैं कि देख लो सरकार की तरफ से होगा, अब किसी को कोई पैसा नहीं, इतना बढ़िया से सब कुछ लगाया जा रहा है। 2020 में सात निश्चय–2 के तहत सभी योजनाओं पर काफी काम हुआ है। जो भी काम बचे हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जायेगा। सात निश्चय–2 के तहत ही युवाओं के लिए दस लाख नौकरी एवं दस लाख रोजगार हम लोगों ने तय किया था, लेकिन

उसके तहत दस लाख युवाओं को नौकरी तो हो ही गयी, लेकिन उसके लिए कुछ और हो रहा था, बढ़ाया गया, तो 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार मिल गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया है, अगला इसी साल से शुरू हुआ है। पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य किया है। आप जान लीजिए कि सरकारी नौकरियों की संख्या और होगी। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अतिपिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो सभी के लिए काम किया गया। मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया गया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गयी एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। पहले वाले देते थे क्या ? पहले वाले नहीं कुछ देते थे। उनके लिए भी हम ही लोगों ने किया, एक–एक काम किया और फिर सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को पहले हर महीने 400 रूपये पेंशन की राशि दी जाती थी, अब जून, 2025 से इसे बढ़ाकर 1100 रूपये कर दिया गया। पहले उन लोगों का 400 ही रखा था, अब पिछले साल हम लोगों ने उसे बढ़ा दिया है 1100 रूपये कर दिया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो गया है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया गया है। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण किया। शुरू में ही किया। 2006 में ही हम लोगों ने पंचायती राज संस्था का, 2007 में नगर निकायों में महिलाओं का और उसके लिए हम लोगों ने तय किया था कि 50 प्रतिशत महिलाएं रहेंगी। तो 50 प्रतिशत महिला और 50 प्रतिशत पुरूष। यह सब कर दिया गया है। हर प्रकार से एक–एक तरह से काम हर तरह से किया गया है और उसके अलावा वही जो कुछ भी होगा, तो आप समझ लीजिए। वर्ष 2013 में पुलिस में 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया शुरू में, बहुत अच्छा दिया गया और वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। पहले स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में सब दिन के लिए था, तो हम लोग जब केंद्र में रहते थे, तो देखते थे, बड़ा अच्छा था। जब यहीं पर हम लोगों की सरकार बनी, तो उसमें देखे कि बहुत कम था। इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में ही स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसे जीविका नाम दिया। जीविका दीदियां उसको हम लोगों ने कर दिया। अब समझ लीजिए कि स्वयं सहायता समूह की संख्या में जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गयी है। उसका शहरी क्षेत्र में नहीं था।

(क्रमशः)

टर्न–16 / संगीता / 05.02.2026

(क्रमशः)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसमें जीविका दीदीयां हो गईं । अब इतना जो किए हैं उसमें 4 लाख 34 हजार जीविका दीदीयां हैं और इसका गठन और लगातार जारी है और इतना ज्यादा हो रहा है और बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है । अब देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा बिहार को सहयोग दिया है । अब आप जान लीजिए जुलाई, 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है और फरवरी, 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोशी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है । वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' का आयोजन हुआ था और पिछले वर्ष 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' का आयोजन बिहार में किया गया जो गौरव की बात है तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं और लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार बिहार आते हैं, आए हैं तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारम्भ किया गया है । इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है तो उस तरह से बिहार में जितना काम और केंद्र सरकार कितना ज्यादा काम इन दिनों चारों तरफ कर रही है और उसका कितना ज्यादा बड़ाई हो रहा है तो अगले 5 वर्षों 2025 से 2030 में विकास की गति को और तेज करने के लिए सात निश्चय–3 जो हमलोगों ने कहा है इस बार के लिए, उसका गठन किया है जिसमें कई काम किए जायेंगे । अब यह जान लीजिए सात राउंड हमलोगों ने कराया है तो पहला है, ''दोगुना रोजगार, दोगुनी आय''– राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है । कुछ पहले से भी काम हुआ है तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये दिए गए हैं । अब इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी, अब अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जायेंगे । नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है और दूसरा है, ''समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार''–अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा । सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी । नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा और तीसरा है, ''कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि''– कृषि विकास का काम और आगे बढ़ाया जाएगा । एक नए बिहार राज्य विपणन प्राधिकार की स्थापना की गई है । अब मखाना, डेयरी एवं मछली पालन के क्षेत्र में विशेष जोर दिया जाएगा और चौथा है, ''उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य''– राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए

एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया गया है और पांचवां हैं, ''सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन''...

(व्यवधान)

पहले सुनिए न, आप बच्चे हो । आपके पिता मेरे समय के न हैं । आपका भी बेटा है, बैठिए...

(व्यवधान)

उसकी शादी भी बाद में हुई थी तो तुमको भी किए हैं न, हम मानते हैं, चलो बैठो, हल्ला मत करो । पांचवां है, ''सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन''– स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा । राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पताओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लायी जाएगी । छठा है, ''मजबूत आधार आधुनिक विस्तार''– आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए शहरी क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, 5 नए एक्सप्रेस–वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का दो–लेन चौड़ीकरण किया जाएगा । सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाये जायेंगे । अब बिहार में पर्यटन एवं इको–टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा और सातवां है, ''सबका सम्मान और जीवन आसान'' ईज ऑफ लिविंग– आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा यानी इस बार के बारे में जो कुछ भी तय कर दिया गया है, 25–30 के लिए, 5 वर्षों में सब काम करने के लिए उसका इस तरह से जो करते हुए सबको कितना फायदा होगा, अब हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है । अब इन दिनों को और आगे बढ़ाया गया है । अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा और इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा, आप जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा । केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है । जो हमने बता दिया है उनका भी सहयोग है । बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा । आप जान लीजिए बिहार देश का कुछ ही राज्य है उसी तरह से बिहार अब बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा, आप चारों तरफ देखते हैं आने–जाने का क्या सुविधा है और कितना लोगों को मिल रहा है नौकरी...

(व्यवधान)

ये आप ही लोग, आप ही लोग अब ठीक हैं न । सब जगह मिल रहा है सबको...

(व्यवधान)

बैठो ना यार, क्यों हल्ला कर रहे हो । कौन जानता है आपको, ध्यान से सुनिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : कुछ नहीं है आपलोगों का....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना अनुमति के नहीं बोलिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अब मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करे । उन्होंने जो बोला है आप देख लीजिए, उन्होंने जितनी बात बोली है...

(व्यवधान)

बैठिए न ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए प्लीज आप । क्यों बीच में बोलते हैं, हर बात में खड़ा होना जरूरी है । संजय जी...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : ये जो उन्होंने किया...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : उसमें भी बहुत सारी बातों का उन्होंने बता दिया है अब ये जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश में कुछ ही राज्य हैं, उसी तरह से बिहार होगा और पूरे बिहार में यहां जो काम होता है और केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है, मिलकर के बहुत आगे बढ़ेगा । इन्हीं शब्दों के साथ उनके माध्यम से जो बात हुई है...

(व्यवधान)

हमने भी कुछ बातें आपको बता दीं हैं कि ये सब हो रहा है तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छे ढंग से कहा है । इन्हीं शब्दों के लिए मैं उनका नमन करता हूं और आप सबलोगों को मैं बधाई देता हूं । आप सब का...

(व्यवधान)

अब एक–दो लोग इधर–उधर क्यों बोलते हैं...

(क्रमशः)

टर्न–17 / यानपति / 05.02.2026

(क्रमशः)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सब बढ़िया हो रहा है और सब को फायदा होगा । हमलोग पूरे बिहार का, सब का फायदा करते हैं तो आपलोगों का भी घर है तो हमलोगों की तरफ से फायदा नहीं होगा, सब को फायदा होगा इसलिए चुपचाप रहिए और इधर–उधर मत जाइये, शांत रहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल के...

(व्यवधान)

शांति बनाए रखें, माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र जी, प्लीज बैठिए । माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री संजय सरावगी,

स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के संशोधन पर विमर्श हुआ । अब मैं एक–एक करके संशोधन और मूल प्रस्ताव को लूंगा ।

क्या माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, संशोधन को स्वीकार किया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–05 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या–27 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक–06 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।